



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 1, 2000/अग्रहायण 10, 1922

No. 276 ]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 1, 2000/AGRAHAYANA 10, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

( पाटन रोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2000

**31/1/99-डीजीएडी.**— 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटन रोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 को धान में रखते हुए

(क) प्रक्रिया

1. जाच के संबंध में नीचे बताई गई प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है:
- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके पश्चात प्राधिकारी भी कहा गया है) को उपरोक्त नियमों के अंतर्गत मैसर्स इस्पात प्रोफाइल इंडिया लि. से घरेलू उद्योग की ओर से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसमें रूस, चीन और यूक्रेन (जिन्हें इसके पश्चात संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित कतिपय सीमलैस ग्रेड के एलॉय और गैर एलॉय स्टील बिलेट्स, बार्स और राउंड्स (जिन्हें इसके बाद संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया था,
- (ii) याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किए गए आवेदन की प्रारंभिक जांच से कुछ कमियों का पता लगा, जिन्हें याचिकाकर्ताओं द्वारा बाद में ठीक कर दिया गया था। इसलिए याचिका को उचित रूप से प्रलेखित माना गया था।
- (iii) प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के खिलाफ जांच प्रारंभ करने का निर्णय लिया। नियमों के उप-नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले प्राधिकारी ने पाटन की जांच हेतु आवेदन प्राप्त होने के बारे में रूस, चीन और यूक्रेन के दूतावासों को सूचित किया,

- (iv) प्राधिकारी ने 09 दिसंबर, 1999 को सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया जिसके तहत संबद्ध देशों के मूल के या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु, जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची -I के सीमाशुल्क कोड 7206.90, 7207.19 और 7207.20 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच शुरू की गई। दिनांक 21.1.2000 को एक शुद्धि पत्र जारी किया गया था जिसमें जांचाधीन ग्रेडों की सूची में कुछ सुधार किए गए थे।
- (v) प्राधिकारी ने सभी ज्ञात निर्यातकों (जिनका ब्यौरा याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराया गया था) और उद्योग संघों को सार्वजनिक सूचनाओं की प्रति भेजी और नियम 6(2) के अनुसार उन्हें लिखित में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अवसर दिया;
- (vi) नई दिल्ली स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को जांच शुरू करने के बारे में नियम 6(3) के अनुसार इस अनुरोध के साथ सूचित किया गया कि निर्धारित समयावधि में प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें। ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची के साथ पत्र, याचिका और निर्यातकों को भेजी गई प्रश्नावली की एक प्रति भी संबंधित दूतावासों को भेजी गई थी;
- (vii) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातकों (जिनका ब्यौरा याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया) को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी और उनसे आग्रह किया गया कि वे पत्र के जारी होने की तारीख से चालीस दिनों के अंदर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराएं। याचिका की प्रति भी अन्य हितबद्ध पार्टियों को मुहैया कराई गई थी;
- (viii) जांच की अवधि सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के ब्यौरे उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय से अनुरोध किया गया;
- (ix) प्राधिकारी ने, जहां तक आवश्यक समझा, याचिकाकर्ताओं के परिसरों की मौके पर जांच की;
- (x) क्षति के बारे में याचिकाकर्ताओं से अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी, जो प्राप्त हो गई थी
- (xi) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश को प्राधिकारी द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया और इसे हितबद्ध पक्षों द्वारा जांच हेतु खुला रखा;
- (xii) इस अधिसूचना में \*\*\*\*\* से किसी हितबद्ध पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना प्रदर्शित होती है और जिसे प्राधिकारी ने नियमों के तहत गोपनीय ही माना है।
- (xiii) यह जांच 1 जनवरी, 1999 से 30 सितम्बर, 1999 तक की अवधि के लिए की गई थी।
- (xiv) सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी) और याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई सूचना के आधार पर भारत में उक्त वस्तुओं के निर्माण और बिक्री की लागत और इष्टतम उत्पादन लागत का निर्धारण करने के लिए लागत जांच भी की गई जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए क्या पाटन सीमा से कम पाटनरोधी शुल्क लगाना पर्याप्त होगा;
- (xv) प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को संगत सूचना भेजने के लिए प्रश्नावली भेजी:-

- 1.) तियांजिन पाइप कारपोरेशन, चीन जनवादी गणराज्य
- 2.) मलटीएरा कोमोडिटीज लि., यूक्रेन
- 3.) चेलिया बिन्सक ट्यूब रोलिंग प्लांट, रूस

- 4.) वोल्सकी ट्यूब मिल, रूस
- 5.) वोल्सकी ट्यूब मिल्स, रूस
- 6.) त्याजप्रोम एक्सपोर्ट, रूस
- 7.) कुंझनेस्की मेट काम्बीनेट, पोबेडी
- 8.) मेग्नीटोगोरस्की मेट काम्बीनेट, किरोवा
- 9.) निजनेटागिलस्की मेट काम्बीनेट, निझनी तागील
- 10.) नोवोलीपेटस्की मेट काम्बीनेट
- 11.) केरीपोवेटस्की मेट काम्बीनेट, मीरा
- 12.) अजोवस्टल मेट काम्बीनेट, लेपोरसकोगो
- 13.) सर्प 1 मोलट, जोलोतोरोजस्की वल
- 14.) दलनेवोस्टोकनी रोल्ड स्टील प्लांट मास्को

(xvi) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगने के लिए निम्नलिखित ज्ञात आयातकों को प्रश्नावली भेजी गई थी:-

- 1.) महाराष्ट्र सीमलैस लि. नई दिल्ली ।
- 2.) कल्याणी सीमलैस ट्यूब्स लि., पुणे ।
- 3.) इंडियन सीमलैस ट्यूब्स लि., पुणे ।
- 4.) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि., तिरुची ।
- 5.) एसोसिएशन ऑफ सीमलैस ट्यूब मैन्फैक्चरर्स, पुणे ।

Xvii जांच शुरुआत संबंधी नोटिस की प्रतियां भी निम्नलिखित को भेजी गई थी:-

- 1.) एसोचैम, नई दिल्ली
- 2.) सी आई आई, नई दिल्ली
- 3.) फिक्की, नई दिल्ली

(xvii) दिनांक 22.5.2000 को निदेशक (पाटनरोधी) के समक्ष विचाराधीन मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षों को अवसर प्रदान किया गया था और दिनांक 16.10.2000 को निर्दिष्ट प्राधिकारी की अध्यक्षता में सार्वजनिक सुनवाई की गई थी ।

(ख) याचिकाकर्ताओं, आयातकों, निर्यातकों, निर्यातक देशों के दूतावासों और अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

## 2. याचिकाकर्ताओं के विचार

मै. इस्पात प्रोफाइल इंडिया लि. ने मै. इंडियन सीमलैड एलाय लि. के समर्थन से घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर की है और अपने अनुरोधों में निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं-

- (i) याचिकाकर्ताओं ने इस्पात तैयार करने की उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी स्थापित करके और 2000 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करते हुए 2,50,000 टी पी ए की विनिर्माण क्षमता के साथ विभिन्न ग्रेडों तथा आकारों के एलॉय और गैर-एलॉय इस्पात का विनिर्माण करने के लिए संयंत्र की स्थापना की थी ।
- (ii) वे इस समय विभिन्न आकारों एवं प्रकारों के इस्पात के सबसे बड़े विनिर्माता हैं और उनका उत्पाद न केवल घरेलू बाजार में अपनी खास पहचान रखता है बल्कि उसे विदेशों से भी अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है । उन्हें "शून्य" दोष युक्त इस्पात की ख्याति प्राप्त है और उन्होंने आई एस ओ 9002 प्रमाणन भी प्राप्त कर लिया है । उनके उत्पाद आयात प्रतिस्थापनीय हैं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को बचाने में मदद करते हैं । उनके निर्यातों से भी 15 करोड़ रु. वार्षिक की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ।
- (iii) उनके उत्पादनों का पारम्परिक इस्तेमाल सीमलैस ट्यूब ग्रेड-बिलेट्स, छड़ियों एवं गोलियों के लिए होता आ रहा है । तथापि, रूस, यूक्रेन तथा चीन के निर्यातकों ने पिछले तीन वर्षों में भारतीय बाजार में कीमत में भारी कमी की है । ये कीमतें 1996-97 में लगभग 350 अमरीकी डालर से घटाकर अप्रैल-दिसम्बर 1998 में 260 अमरीकी डालर कर दी गई हैं । वस्तुतः इन कीमतों को पहले ही घटाकर 209 अमरीकी डालर प्रति मी.टन के स्तर पर ला दिया गया है । भारत को वस्तुओं के निर्यात में अंतर्ग्रस्त खर्चों पर विचार करते समय यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्यातकों द्वारा उत्पादन की परिवर्ती लागत से कम कीमत पर बिक्री की जा रही है । स्पष्टतः वस्तुओं का भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है । इससे इन प्रचालनों पर इस हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है कि उन्हें सीमलैस ट्यूब ग्रेडों की छड़ियों, बिलेट्स और गोलियों के लिए मुश्किल से ही कोई आदेश मिला हो ।
- (iv) आई एस पी ए टी देश में इस ग्रेड की सामग्री का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है । आई एस एस ए एल और कल्याणी स्टील्स लि. भी इन ग्रेडों की सामग्री का उत्पादन करते हैं । हास्पेट में भी क्षमता स्थापित की जा रही है । यद्यपि आई एस पी ए टी सीमलैस ग्रेड के एलॉय और गैर-एलॉय इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है, तथापि, आई एस एस ए एल जैसे अन्य उत्पादकों ने याचिका का समर्थन किया है । इन देशों से हुए पाटन से न केवल मौजूदा उत्पादकों को वास्तविक क्षति हुई है अपितु इसके परिणामस्वरूप नई कंपनियों की स्थापना में भी भारी रूकावट आएगी ।
- (v) देश में किए जा रहे भारी पाटन, जिसके परिणामस्वरूप आई एस पी ए टी को अत्यधिक घाटा हुआ है, को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने सीमलैस ग्रेड के एलॉय और गैर-एलॉय इस्पात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है ।

### 3. भारत में रूसी परिसंघ के व्यापारिक प्रतिनिधि के विचार

- (i) प्रथमतः याचिका तथा अधिसूचना में प्रयुक्त जांच की विषय वस्तु की परिभाषाओं में कुछेक विरोधाभास तथा लगतियां हैं । सीमा शुल्क अथवा किसी अन्य सरकारी आंकड़ों में "कुछेक सीमलैस ग्रेड के एलॉय और गैर-एलॉय इस्पात के बिलेट्स, छड़ियों, गोलियों" जैसी कोई श्रेणी नहीं है । केवल "बिलेट्स, छड़ियां, गोलियां" जैसी परिभाषा का संदर्भ लेकर सत्यापन किया जा सकता है और इसप्रकार उस पर ही विचार किया जा सकता है ।
- (ii) द्वितीयतः, भारतीय उत्पादकों की सूची में याचिकाकर्ता द्वारा उल्लिखित केवल चार कंपनियों को ही शामिल नहीं किया जाना चाहिए बल्कि सेल, एस्सार, जिंदल, टाटा आदि

जैसे अन्य उत्पादकों को भी शामिल किया जाना चाहिए और तदनुसार उनके उत्पादन के कुल क्षेत्र पर विचार किया जाना चाहिए। 'स्टील सिनेरियो स्टेटिकल ईयरबुक 1999' के अनुसार, वर्ष 1998-99 में भारत में बिलेट्स, छड़ियों एवं गोलियों का कुल उत्पादन 12,466 हजार टन का हुआ था। उन्होंने आगे बताया है कि कुल भारतीय उत्पादन में याचिकाकर्ता का हिस्सा काफी कम है और इस लिए आवेदन की वैधता के बारे में गंभीर शंका है।

- (iii) जहां तक रूसी मूल के निर्यातों का संबंध है, उनसे भारतीय घरेलू उद्योग किसी भी रूप में प्रभावित नहीं हो सकता क्योंकि याचिका तथा "भारत में विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी" में यथा उल्लिखित रूसी मूल के निर्यातों का हिस्सा कुल भारतीय उत्पादन का केवल 0.18 प्रतिशत अथवा 0.72 प्रतिशत बनता है, जैसाकि उपरोक्त (ii) में दिया गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रूस से हुए आयातों और घरेलू उद्योग को हुई आरोपित वास्तविक क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- (iv) उपरोक्त के अलावा, हमें इस तथ्य का कोई भरोसेमंद स्पष्टीकरण नहीं मिला है कि जापान से हुए आयातों को ध्यान में नहीं रखा गया है यद्यपि उनकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है और उनकी औसत कीमतें (जिन्हें याचिका में दिए गए आंकड़ों का इस्तेमाल कर निकाला जा सकता है) रूसी औसत कीमतों की लगभग आधी हैं।
- (v) जहां तक वास्तविक रूसी कीमतों का संबंध है, "आस्कल इलैक्ट्रो मेटाल जिकल कंबीनेट" के उत्तरों में दिए गए कीमतों के ब्यौरे से साफ तौर पर यह स्पष्ट होता है कि ये कीमतें पाटनकारी कीमतें नहीं हैं।
- (vi) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम यह समझते हैं कि साधारण तौर पर इस जांच को उसके लिए सही, तथ्यपरक एवं सत्यापित सूचना के अभाव में समाप्त कर दिया जाना चाहिए। किसी भी हालत में, खासकर रूसी उत्पादकों के खिलाफ कोई पाटनरोधी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

#### 4. यूक्रेन के आर्थिक मंत्रालय के विचार:

- (क) जांच संबंधी क्रियाविधि का उल्लंघन हुआ है क्योंकि उत्पाद का संपूर्ण विवरण, कीमतों, जांच शुरू करने की तारीख और आरोपित पाटित आयातों की मात्रा के बारे में सूचना नहीं दी गई है,

(ख) याचिका में समान वस्तु के बारे में पर्याप्त सूचना और साक्ष्य तथा उन कीमतों के बारे में साक्ष्य निहित हैं, जिन पर यूक्रेन के मूल के जांचाधीन उत्पाद की भारत को बिक्री की गई थी;

(ग) यह भी तर्क दिया गया है कि यूक्रेन के सरकारी आंकड़ों के अनुसार जांच अवधि के दौरान इस उत्पाद का यूक्रेन से भारत को निर्यात होने का कोई साक्ष्य नहीं है ।

(घ) अतः अनुरोध है कि यूक्रेन को जांचाधीन देशों की सूची में से हटा दिया जाए ।

#### 5. आयातकों, उपयोक्ताओं तथा एक रूसी निर्यातक मै.ओ. ई. एम. के. के अनुरोध

मै. महाराष्ट्र सीमलैस लि. तथा मै. ओ ई एम के, रूस के काउंसिल द्वारा उठाए गए मुख्य मुख्य मुद्दे निम्नानुसार हैं-

(क) जांचाधीन उत्पाद क्या है ? दूसरे शब्दों में, वह उत्पाद, जिस पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाएगा (जांचाधीन उत्पाद)

(ख) इस प्रकार से अभिज्ञात उत्पादों के लिए क्या याचिका में नियम 5(3) (क) के तहत अपेक्षित स्थिति निर्दिष्ट है ? (याचिका दायर करने की स्थिति संबंधी प्रश्न)

(ग) प्रथम दृष्टया कारणात्मक संबंध की वजह जापान से हुए आयात हैं अथवा इसकी वजह जांचाधीन तीनों देश हैं ।

इन मुद्दों में किए गए अनुरोधों पर नीचे निष्कर्षों में समुचित स्थानों पर विस्तार से चर्चा की गई है । उपरोक्त के अलावा, फेडरेशन आफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज आफ इंडिया, आल इंडिया स्टील रोलर्स एसोसिएशन, प्रभात स्टील ट्रेडर्स, ईगल स्टील्स इत्यादि से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जो निर्दिष्ट ग्रेडों के एलॉय/गैर-एलॉय इस्पात के बिलेट्स, छड़ियों एवं गोलियों के उपयोक्ता/आयातक हैं । इन अभ्यावेदनों में उन्होंने उठाए गए मुद्दों पर अपनी टिपणियां दी हैं, जिन पर भी नीचे विचार किया गया है ।

**ग. उठाए गए मुद्दों की जांच**

6. याचिकाकर्ता, निर्यातकों और आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों की उस सीमा तक जांच कर उन पर विचार किया गया है जहां तक वे नियमों के अनुसार संगत हैं और जहां तक वे इस मामले पर प्रभाव डालते हैं और उन पर इन निष्कर्षों में उपयुक्त जगहों पर विचार किया गया है।

**घ. विचाराधीन उत्पाद**

7. जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में दिए गए विवरण के अनुसार, जांच में शामिल उत्पाद "रुस, चीन, युक्रेन मूल के कुछेक सीमलैस ग्रेड के अलॉय और गैर-अलॉय स्टील बिलेट्स, बार और रॉउण्ड" हैं। यह उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमाशुल्क उप शीर्ष 7206.90, 207.19 और 7207.20 के अंतर्गत आता है जो केवल सांकेतिक हैं और इस जांच के दायरे पर किसी रूप से बाध्यकारी नहीं है। जांचाधीन अलॉय और गैर-अलॉय स्टील, बिलेट्स, बार और राउण्ड के ग्रेडों का उल्लेख जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में किया गया है और जिसे दिनांक 21.1.2000 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित किया गया है। ये ग्रेड हैं :

क्रम सं०	आई एस विनिर्देशन	समतुल्य अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशन
1	आईएस, 1875 सीएल 1	एएसटीएम, एसए 192, एपी15एल ग्रेड X 42
	(गैर-अलॉय स्टील)	बी53059पीटी-2ग्रेड 243, डीआईएन, सीके 15
2	आई.एस 1875, सीएल 1ए	एसआई 1018, एएसटीएमए 333

	(गैर-अलॉय स्टील)	
3	आई.एस 1875, सीएल 2	एसए 1026
	(गैर-अलॉय स्टील)	
4.	आई.एस 1875, सीएल 2ए	एसटीएम, एसए210ए1, एपी1 एसएल ग्रेड बी
	(गैर-अलॉय स्टील)	एपीआईएसएल ग्रेड X 46, एपीआईएसएल X -46
5	आई.एस 1875, सीएल 3	एसटीएम, एसए210 ग्रेड सी, एसई 1030
	(गैर-अलॉय स्टील)	
6	आई.एस 1875, सीएल 3ए	एसई 140, एमई 1035
	(गैर-अलॉय स्टील)	
7	आई.एस 1875, सीएल 4	बीएस, ईन 8 डी
	(गैर-अलॉय स्टील)	
8	आई.एस 1875, सीएल 5	एसई 1050
	(गैर-अलॉय स्टील)	
9	आई.एस 5517, 27सी 15	एसई 1530
	(गैर-अलॉय स्टील)	
10	आई.एस 5517, 37 सी 15	बीएस, ईएन 15, एसई 1541
	(गैर-अलॉय स्टील)	
11	आई.एस 4432, 10 सी 4	एसटीएम, एसए 179, एसई 1010



	(गैर-अलॉय स्टील)	एसएई 1008
12	आई.एस 4368, 20एमएन 2	डीआईएन 2391 एसटी 52, एसएई 1518
	(गैर-अलॉय स्टील)	
13	आई.एस 5517, 35एमएन6एमओ3	एपीआई एन80, एसएई4042
	(गैर-अलॉय स्टील)	
14	आई.एस समतुल्य नहीं	एसएई4130
	उपलब्ध(अलॉय स्टील)	
15	आई.एस समतुल्य नहीं	एसएई4118(निकटतम)
	उपलब्ध(अलॉय स्टील)	
16	आई.एस समतुल्य नहीं	बीएस 3602 पीटी 1500 एनबी
	उपलब्ध(अलॉय स्टील)	(माइक्रोअलॉयड स्टील)
17	आई.एस समतुल्य नहीं	बीएस 3059 पीटी11 ग्रेड 440
	उपलब्ध (गैर-अलॉय स्टील)	
18	आई.एस समतुल्य नहीं	एसएई 1518
	उपलब्ध (गैर-अलॉय स्टील)	
19	आई.एस 4398, 103 सीआर2,	एसएई 52100
	(अलॉय स्टील)	
20	आईएस 4368 20 एमएन सीआर 1	20 एमएनसीआरएस
21	आईएस 3749 टी 105 सी आर 5	
22	आई एस 3930 40 सीआर4 एमओ 3	

23	आई एस 4368 21 सीआर 1 एमओ 28	
24	आई एस 5517 27 सीएल 5 + एमओ	
25	आई एस 4432 सीएलओ	एमएसएल 4ए
26	आई एस 5517 37 सीएल 5	
27	आई एस 4368 37 एसएल 2 एमएन 90	
28	आई एस 5517 3795 37 सीएल 5+ एमओ	
29	आई एस 4368 40 एनआई 2 सीआर 1 एमओ 28	

इस मुद्दे पर विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए तर्क निम्नलिखित हैं :

#### **8. आयातकों और निर्यातकों द्वारा दिया गया तर्क**

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना और प्रश्नावली के अपने उत्तर में आयातकों और निर्यातकों के काउंसेल ने निम्नलिखित तर्क दिए थे:

(क) याचिका के अगोपनीय अंश के भाग 1 के अनुसार, कथित रूप से पाटित किया जाने वाला उत्पाद 70 मिमी से 250 मिमी व्यास वाले कुछेक ग्रेड के अलॉय और गैर-अलॉय स्टील बिलेट्स, बार्स, राउन्ड हैं। याचिका में आगे कहा गया है कि संबद्ध वस्तुओं के अनेक प्रयोग हैं। आगे यह कहा गया है कि संबद्ध वस्तु का उपयोग मुख्य रूप से और बड़े पैमाने पर सीमलैस ट्यूब के उत्पादन में किया जाता है। यह भी संकेत दिया गया है कि उक्त ग्रेडों का उपयोग सीमलैस ट्यूब्स/पाइपों के विनिर्माण में और कुछ गढ़ाई प्रयोगों में भी होता है और यह कि इसका मुख्यतः सीमलैस ट्यूब्स/पाइपों के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार याचिकाकर्ता की दलील से यह देखा जा सकता है कि उक्त आकार के बिलेट्स, बार और

राउन्ड का उपयोग सीमलैस ट्यूब्स/पाइपों के विनिर्माण के साथ अन्य उपयोगों के लिए भी किया जाता है। याचिकाकर्त्ताओं ने "सीमलैस ग्रेड" शब्द का प्रयोग अन्यत्र कहीं नहीं किया है।

(ख) तथापि, दिनांक 9.12.99 की जांच शुरुआत संबंधी सूचना के पैरा 2 में शामिल उत्पाद का उल्लेख रुस, चीन और उक्रेन के मूल के या वहां से निर्यातित कुछेक सीमलैस ग्रेड के अलॉय एवं गैर अलॉय स्टील के बिलेट्स, बार, राउन्ड" के रूप में किया गया है। जांच शुरुआत संबंधी सूचना में "कुछ सीमलैस ग्रेड" शब्दों का प्रयोग किया गया था जिनका याचिका में उल्लेख नहीं मिलता है। उसी प्रकार याचिका में संबद्ध वस्तुओं के उल्लिखित 70 मिमी से 250 मिमी के व्यास को जांच शुरुआत संबंधी सूचना में हटा दिया गया है। विचाराधीन उत्पाद के दायरे को प्राधिकारी ने व्यापक बना दिया है। अकेले इस आधार पर जांच शुरुआत अनुचित है।

(ग) जहां तक उत्पाद के विनिर्देशन का संबंध है, इस प्रश्न का निराकरण करना होगा कि क्या कुछेक सीमलैस ग्रेड के अलॉय और गैर अलॉय स्टील बिलेट्स, बार, राउन्ड के नाम से कोई श्रेणी है। याचिकाकर्त्ता ने उत्पादों के विनिर्देशन के रूप में आई एस 1875, आई एस 3749, आई एस 3940, आई एस 5517, आई एस 4432 और आई एस 4368 जैसे विभिन्न ग्रेडों का उल्लेख किया है। उपलब्ध तकनीकी सामग्री से यह प्रदर्शित होता है कि इन ग्रेडों का उपयोग औजारों एवं रंजकों को बनाने और सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इस्पात हेतु विनिर्देशन के रूप में उल्लिखित इन ग्रेडों में से कुछ ग्रेडों का उपयोग कड़ापन लाने और पानी चढ़ाने के लिए किया जाता है। इसलिए यह पूर्णतः स्पष्ट है कि केवल सीमलैस ट्यूब बनाने के अतिरिक्त भी इन ग्रेडों के बहुत से उपयोग हैं जैसाकि याचिकाकर्त्ताओं ने याचिका के अगोपनीय अंश में उल्लेख किया है।

(घ) पाटनरोधी शुल्क अंतिम उपयोग पर आधारित नहीं हो सकता क्योंकि याचिकाकर्त्ता का उद्देश्य सीमलैस ट्यूब के विनिर्माताओं द्वारा केवल निर्दिष्ट ग्रेडों के आयात पर शुल्क लगवाने का प्रतीत होता है। इसके अलावा जांच के परिणामस्वरूप ऐसे स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें संबद्ध देशों

से आयातित विलेट्स, बार, राउन्ड के प्रत्येक खेप को सीमाशुल्क विभाग द्वारा रोकना पड़ेगा ताकि यह निर्धारण करने हेतु जांच की जा सके कि क्या उक्त मद पाटनरोधी शुल्क लगने वाले प्रकार की है अथवा नहीं जिसके परिणामस्वरूप समग्र व्यवधान पैदा होगा । पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश बिलेट्स बार और राउन्ड्स पर नहीं की जा सकती क्योंकि यह जांच केवल विशिष्ट ग्रेडों के बारे में है और क्योंकि संबद्ध वस्तुओं का दूसरे प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने वाले आयातक और उपयोक्ताओं को इस जांच में शामिल नहीं किया गया है । याचिकाकर्त्ताओं द्वारा ऐसे कुछ ग्रेडों जो अनन्य रूप से सीमलैस प्रयोग हेतु आशयित नहीं हैं, को चुने जाने का कार्य दुर्भावनापूर्ण है और यदि प्राधिकारी उनके अन्तिम उपयोग का संदर्भ लिए बिना इस प्रकार के आधार पर जांच करते हैं और उन्हीं आधारों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं तो ऐसा करने का तात्पर्य दूसरे प्रयोगों के लिए आशयित उक्त ग्रेडों पर शुल्क लगाने से होगा । इस प्रकार की कार्रवाई उल्लंघनकारी है क्योंकि उक्त ग्रेड के अन्य उपयोक्ताओं को अधिसूचित नहीं किया गया है । ऐसी ही स्थिति याचिकाकर्त्ता से भिन्न उक्त ग्रेडों के बिलेट्स/राउन्ड्स के सभी उत्पादकों की है । दूसरी ओर यदि केवल अन्तिम उपयोग के आधार पर उक्त ग्रेडों पर शुल्क लगाने की मांग की जाती है, तो इस प्रकार की सिफारिश "केटेलिस्ट मामले" में सीगेट के निर्णय के प्रतिकूल होने के अलावा, सीमाशुल्क विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जाने के योग्य नहीं है ।

(ड.) इसके अलावा, फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, प्रभात स्टील ट्रेडर्स, ईगल स्टील्स और आल इंडिया स्टील रीरोलर्स एसोसिएशन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन में भी सीमलैस पाइप/ट्यूब बनाने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए विशिष्ट ग्रेडों के वैकल्पिक उपयोग पर जोर दिया गया है और सीमलैस ट्यूब के विनिर्माताओं के अलावा अन्य उपयोक्ताओं को आपूर्ति करने वाले अन्य उत्पादक होने के कारण याचिकाकर्त्ताओं की स्थिति पर एतराज किया है ।

**9. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध:** अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा उठाए गए मुद्दों के जवाब में याचिकाकर्ताओं ने अपने अनुरोधों में बताया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए किए गए उनके अनुरोध में उनके द्वारा बताया गया विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार है:-

" भारत में पाटित किए जा रहे उत्पाद का नाम है - कुछेक प्रकार के एलॉय तथा गैर-एलॉय स्टील बार्स, बिलेट्स तथा राउंड्स, जिनका व्यास 70 मिमी से 250 मिमी तक है और जो आई एस विनिर्देशनों अथवा आई एस मानकों के समतुल्य अन्य अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशनों के अनुरूप हैं। आई एस विनिर्देशनों तथा रासायनिक संयोजनों की सूची इस याचिका के साथ संलग्न है। "

**10.** अनुरोध है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी की गई जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना को उद्धृत करते समय विरोधकर्ता हितबद्ध पार्टियों ने विवरण की केवल प्रथम पंक्ति ही पढ़ी है और उन्होंने दूसरी पंक्ति को नजरअंदाज कर दिया है। जिसमें विवरण का बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है। जांच शुरुआत संबंधी सूचना में निम्नानुसार उल्लेख है - ,

" जांच में शामिल उत्पाद रूस, चीन तथा उक्रेन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कुछेक सीमलैस ग्रेड के एलॉय तथा गैर-एलॉय स्टील बिलेट्स, बार्स तथा राउंड्स हैं। याचिकाकर्ताओं ने एलॉय तथा गैर-एलॉय स्टील बिलेट्स, बार्स तथा राउंड्स के केवल निम्नलिखित ग्रेडों पर ही पाटनरोधी शुल्क लगाने की मांग की है। "

**11.** यद्यपि महाराष्ट्र सीमलैस लि० ने तर्क दिया था कि सम्बद्ध वस्तुओं का उपयोग काफी व्यापक है और उन्होंने यह विश्वास दिलाने की भी कोशिश की है जैसे कि सम्बद्ध वस्तु बहुत सी कंपनियों द्वारा बड़ी मात्रा में खपत की जा रही हो तथापि वास्तविकता यह है कि सीमलैस पाइप के उत्पादकों को छोड़कर किसी अन्य पार्टी ने प्राधिकारी को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने और अपने हितों का जिक्र करने की परवाह नहीं की है। सुनवाई के समय उन्होंने फेडरेशन ऑफ

इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों से विशेष रूप से यह अपेक्षा की थी कि सम्बद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं, उनकी वार्षिक आवश्यकताओं और घरेलू स्रोतों से सम्बद्ध वस्तु की तीन वर्ष की खरीद तथा आयातों के संबंध में ब्यौरे प्राधिकारी को उपलब्ध कराए जाएं ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि कुछ ऐसी अन्य हितेबद्ध पार्टियां भी हैं जो इस सामग्री की पर्याप्त मात्रा में खपत करती हैं।

अनुरोध है कि ऐसी सूचना आज की तारीख तक इन पार्टियों से प्राप्त नहीं हो रही है।

12. आयातकों द्वारा किए गए अनुरोधों तथा निर्यातक मै0 ओ ई एम के, रुस द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब से स्पष्टतः यह पता चलता है कि उन्होंने वह उत्पाद समझा है जिसका मुख्य रूप से सीमलैस ट्यूब, पाइपों के विनिर्माण के लिए उपयोग किया जा रहा है, जिसे सीमलैस ग्रेड का समझा जाता है। यह प्रश्न तथ्यपरक प्रश्न है कि क्या सम्बद्ध वस्तु सीमलैस ट्यूब के उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से तथा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जा रही है। रिकार्ड में उपलब्ध तथ्य से यह पता चलता है कि सम्बद्ध वस्तु की लगभग समस्त मांग उन उत्पादकों की ओर से की गई है जिन्होंने इसकी खरीद सीमलैस ट्यूबों के विनिर्माण के लिए की है। इसके अतिरिक्त, जिन कंपनियों के उत्पादन और बिक्री की सूचना हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई है, वे कंपनियां सम्बद्ध वस्तुओं के उत्पादकों के एक बड़े अनुपात का प्रतिनिधित्व करती हैं।

13. महाराष्ट्र सीमलैस लि0 की आपत्ति यह है कि आकार के संबंध में जांच के दायरे को बढ़ाने तथा अंतिम उपयोग पर आधारित जांच के क्षेत्र को सीमित करने, दोनों के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी की कार्रवाई अवांछनीय है। चूंकि यह आपत्ति केवल जांच के दायरे के बारे में है, इसलिए इसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निष्कर्षों को दर्ज करते समय सर्वदा उचित रूप से संशोधित किया जा सकता है। वास्तव में, कानून के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह जांच करने के लिए प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क की गुंजाइश की जांच करे। यद्यपि दायरे को हमेशा बाद की जांच में सीमित किया जा सकता है तथापि इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। इस प्रकार इस दायरे को उन क्षेत्रों तक सीमित किया जा सकता है, जिन क्षेत्रों में हमने शुल्क की

मांग की है। अनुरोध है कि उत्पाद विवरण में किसी संशोधन का अभिप्राय विचाराधीन उत्पाद में किसी संशोधन से नहीं है।

14. अनुरोध है कि विरोधकर्ता हितबद्ध पार्टियां जोरदार तरीके से यह तर्क दे रही हैं कि सीमलैस बनाने के बारे में याचिका में दिए गए आई एस विनिर्देशनों में भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस संबंध में हमारा अनुरोध है कि सीमलैस निर्माण और कुछ नहीं है बल्कि गढ़ाई संबंधी एक अनुप्रयोग है।

15. यह तर्क दिया गया है कि यदि शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है तो केन्द्रीय सरकार शुल्क लगाने की स्थिति में नहीं होगी और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को अनावश्यक कठिनाई होगी। इस संदर्भ में अनुरोध है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव स्रोत पर निर्भर रहते हुए उसी उत्पाद पर विभेदी शुल्क के रूप में पड़ता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य मामलों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के आदेशों के कार्यान्वयन से यह नतीजा निकलता है कि इस मामले में भी पाटनरोधी शुल्क लगाने के आदेश के कार्यान्वयन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह मानते हुए यद्यपि इसे स्वीकार न करते हुए कि शुल्क को लागू करने में कुछ कठिनाइयां होंगी, इसका अर्थ यह नहीं निकलता है कि घरेलू उद्योग को नियमों के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त करने के उसके अधिकार से वंचित कर दिया जाना चाहिए।

अंतर्गत संरक्षण प्राप्त करने के उसके अधिकार से वंचित कर दिया जाना चाहिए।

16. यह तर्क दिया गया है कि विचाराधीन उत्पाद का उल्लेख उसके अन्तिम उपयोग और तदनुसार उस पर लगाए गए शुल्कों के आधार पर नहीं किया जा सकता। अनुरोध है कि उत्पाद का उल्लेख ऐसी अनेक विशेषताओं के संबंध में किया जाता है, जिन्हें किसी उत्पाद में विद्यमान समझा जाता है और इन विशेषताओं में से एक विशेषता है - उस उत्पाद का उपयोग। अतः जिस प्रयोजन हेतु उत्पाद का प्रयोग किया जाता है उसका उल्लेख किए जाने का तात्पर्य यह नहीं है कि शुल्क की मांग केवल उसी खास अंतिम उपयोग के संबंध में ही की जा रही है।

**17. प्राधिकारी द्वारा जांच:**

उत्पाद का विवरण देने के अतिरिक्त, प्राधिकारी के विशेष रूप से उन ग्रेडों का उल्लेख किया था जिन पर याचिकाकर्ता द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाने की मांग की गई थी जिससे जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में आए शब्द "सीमलैस" ग्रेड द्वारा उत्पन्न गलतफहमी को दूर हो जाना चाहिए। तथापि, बिलेट्स, बार्स तथा राउंड्स की मोटाई, जिन पर शुल्क लगाने की मांग की गई थी, के बारे में असावधानीवश सूचना नहीं दी गई थी। घरेलू उद्योग का तर्क स्वीकार करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उत्पाद के विवरण को "कुछेक ग्रेडों के एलॉय तथा गैर एलॉय स्टील बिलेट्स, बार्स तथा राउंड्स, जो आई एस विनिर्देशनों अथवा आई एस मानकों के समतुल्य किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशन के अनुरूप हैं, जैसा कि उपरोक्त पैरा 7 में बताया गया है" के रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया। इस प्रकार निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच को भी 70-250 मिमी व्यास के आकारों तक सीमित कर दिया। ग्रेडों की सूची, जो कि दिनांक 9.12.99 की जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना और 21.1.2000 के शुद्धिपत्र में दी गई है, वही रहती है और तदनुसार निष्कर्ष जारी किए जा रहे हैं।

#### **ड. समान वस्तु**

**18** याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित की जा रही सम्बद्ध वस्तु की विशेषताएं सम्बद्ध देशों से आयात की जा रही वस्तु से काफी हद तक मिलती हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु तथा सम्बद्ध देशों से आयातित वस्तु को उपभोक्ताओं द्वारा तय किए गए कुछेक खास तकनीकी विनिर्देशनों के अनुसार होना चाहिए और ये वस्तुएं वास्तव में समान प्रकृति की हैं।

विरोधकर्ता हितबद्ध पार्टियों द्वारा आगे यह भी तर्क दिया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच आरंभ करने में असंगत दृष्टिकोण अपना रहे हैं।



19. यह तर्क दिया गया है कि सीमलेस ट्यूब्स/ पाइप्स के संबंध में पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी ने इन तर्कों की अनदेखी करते हुए जांच शुरू कर दी है और प्रारंभिक निष्कर्षों को प्रकाशित कर दिया है कि केंसिंग, ट्यूब और लाइन पाइप्स विशिष्ट अंतिम प्रयाग के लिए हैं और इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। प्राधिकारी का विचार यह है कि सीमलेस ग्रेड बिलेट्स, बार्स और राउंड्स जैसी कोई वस्तु है और इस प्रकार उसका उपयोग केवल सीमलेस ट्यूब्स को बनाने में किया जा सकता है, तथ्यतः सही नहीं है, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है। अगर यह तर्क सही है तो विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए केंसिंग/उत्पादन/लाइन पाइपो को एकल उत्पाद के रूप में नहीं माना जा सकता है। दोनों मामलों में निर्दिष्ट प्राधिकारी सही नहीं हो सकते।

## 20. प्राधिकारी द्वारा जांच

सीमलेस ट्यूब्स/पाइप्स के आयातों के खिलाफ पाटनरोधी जांच से संबंधित मामले में, यह उल्लेख किया जा सकता है कि लाइन पाइप, केंसिंग पाइप और बॉयलर पाइप के लिए क्रमशः 7304.10, 7304.29, और 7304.39 की अलग-अलग सीमा शुल्क वर्गीकरण संख्याएं हैं। इससे यह स्पष्ट तौर पर यह पता चलता है कि इन पाइपो का विभिन्न विशेषताओं के संबंध में अलग से परिभाषित किया जाता है और आयात के समय, अलग से सीमाशुल्क उप-शीर्ष का उल्लेख करना होता है। यह विचार करते हुए कि सीमलेस ट्यूब्स/पाइप्स की ये अलग-अलग किस्में हैं इन विशिष्ट सीमाशुल्क वर्गीकरणों के संबंध में निष्कर्षों में अलग-अलग शुल्कों की सिफारिश की गई है।

21. उपरोक्त निर्णय के अनुसार उत्पाद के वर्णन में संशोधन (सीमलेस शब्द को छोड़ते हुए) किए जाने से आयातकों द्वारा उठाया गया मुद्दा निरर्थक हो गया है। साथ ही निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह तर्क कभी नहीं रहा था कि संबद्ध वस्तु के विशिष्ट ग्रेडों का उपयोग केवल सीमलेस ट्यूब के बनाने में किया जाता है। उपरोक्त को देखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद को उपरोक्त नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयात की जा रही वस्तुओं के "समान वस्तु" के रूप में बेचा जा रहा है।

## (च) घरेलू उद्योग, याचिकाकर्ता और समर्थक का संबंध और स्थिति

## 22. पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) में यह अपेक्षित है-

उप-नियम (1) के अंतर्गत दिए गए किसी आवेदन के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी कोई जांच तब तक शुरू नहीं करेगा जब तक कि:-

"(क) समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों द्वारा आवेदन के समर्थन अथवा उसके विरोध के प्रभाव की जांच के आधार पर वह यह निर्धारित न कर ले कि उक्त आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया गया है ;

"किन्तु उस स्थिति में कोई जांच शुरू नहीं की जाएगी यदि याचिका का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का हिस्सा घरेलू उद्योग द्वारा किए गए समान वस्तुओं के कुल उत्पादन का 25% से कम बनता हो ....."

**स्पष्टीकरण:-** इस नियम के प्रयोजनार्थ आवेदन को उस स्थिति में घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी और से किया गया समझा जाएगा यदि इसका समर्थन उन घरेलू उत्पादकों द्वारा किया गया हो, जिनका सामूहिक उत्पादन आवेदन का समर्थन अथवा विरोध करने वाले, जैसाभी मामला हो, घरेलू उद्योग के उस भाग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन का 50% से अधिक बनता हो" ।

### 23. स्थिति एवं संबंध

याचिका का विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पाटनरोधी नियमों के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग को इस प्रकार परिभाषित किया गया है ताकि उसमें सामान वस्तु के विनिर्माण में लगे सभी घरेलू उत्पादकों को शामिल किया जा सके । तथापि, उक्त उत्पादक आरोपित पाटित वस्तुओं के आयातकों से जुड़े थे और उन्हें छोड़ा जा सकता है । आगे यह अनुरोध किया गया है कि याचिका का समर्थन मैसर्स इंडियन सीमलैस स्टील एलाय लि. (आईएसएसएल) इंडिया सीमलैस मैटल ट्यूब लि. (आईएसएमटी) से जुड़ा है, जिसने जांच अवधि में संबद्ध वस्तु का आयात किया है । आगे यह भी बताया गया है कि मैसर्स आईएसएसएल तथा आईएसएमटी का सामान्य अध्यक्ष है और उसके तीन सामान्य निदेशक हैं और आईएसटीएल, आईएसएसएल में 1.1 करोड़ रूपए मूल्य के शेयर धारित करती है ।

24. विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षों द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा उल्लिखित उत्पादकों को छोड़कर बिलैट्स, बार्स और राऊंड्स के उत्पादक भी हैं । अगर देश में उत्पादित बिलैट्स, बार्स और राऊंड्स के सभी ग्रेडों को लिया जाए तो वर्ष 1998-99 में तकरीबन 7.5 मिलियन मी. टन बिलैट्स का उत्पादन किया गया है और याचिकाकर्ता और समर्थक द्वारा किया गया उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का मात्र 2% है जिसका अर्थ यह होगा वे याचिका दायर करने की स्थिति में नहीं है । आगे यह तर्क दिया गया है कि याचिका में उल्लिखित ग्रेडों का भी जांच अवधि के दौरान सेल और महिन्द्रा यूजीन स्टील कं. लि. (एमयूएससीओ) द्वारा उत्पादन किया गया है । मैसर्स महाराष्ट्र सीमलैस लि. ने जांच अवधि के दौरान सेल और एमयूएससीओ से संबद्ध वस्तु की क्रमशः 346 मी.टन और 278 मी. टन की खरीद की है ।

25. उपरोक्त तर्कों के आधार पर हितबद्ध विरोधकर्ता पक्षों ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता और समर्थकों के पास घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के बारे में सुने जाने का कोई अधिक नहीं है और तदनुसार जांच समाप्त कर दी जानी चाहिए ।

## 26. प्राधिकारी द्वारा जांच

निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच शुरू किए जाने से पहले और हितबद्ध विरोधकर्ता पक्षों द्वारा किए गए निवेदनों के पश्चात भी स्टील उद्योग से जुड़ी विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारत में स्टील के प्रमुख उत्पादकों से संपर्क किया ताकि संबद्ध ग्रेडों के लिए घरेलू उद्योग की स्थिति का पता लगाया जा सके। उनके जवाबों में यह बताया गया है कि मैसर्स विश्वेसरैया आइरन एवं स्टील लि. सेल की एक सहायक कम्पनी, ने 1998-99 में उक्त ग्रेडों का 1132 मी. टन की उत्पादन किया और याचिका में उल्लिखित उत्पादकों को छोड़कर अन्य उत्पादकों के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। इसलिए, उपलब्ध सूचना के आधार पर, याचिका में विनिर्दिष्ट एलॉय और गैर-एलॉय बार्स, बिलेट्स और राऊंड्स के कुछ ग्रेडों का उत्पादन याचिका में उल्लिखित उत्पादन पर्याप्त रूप से अधिक होने का कोई साक्ष्य नहीं है। स्थिति के प्रश्न पर विचार करते समय उत्पादन क्षमता की मौजूदगी अपने-आप में संगत नहीं है। "स्थिति" का निर्धारण घरेलू उद्योग में समर्थकों के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए संबद्ध वस्तु के वास्तविक उत्पादन में हिस्से से संबंधित साक्ष्य के आधार पर करना होता है।

27. जहाँ तक संबंध का प्रश्न है, याचिका का विरोध कर रहे हितबद्ध पक्षों ने आईएसएमटी से जुड़े होने के कारण आईएसएसएल के मुद्दों को उठाया है, जो उक्त ग्रेडों के आयातक हैं। सत्यापन करने पर यह पाया गया था कि आईएसएमटी द्वारा किए गए आयात शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत आते हैं और इस प्रकार इसकी देश के वाणिज्य में प्रविष्टियां नहीं की गई हैं। दिनांक 15.07.99 को पाटनरोधी नियमों में किए गए संशोधन के द्वारा, निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास घरेलू उद्योग की परिभाषा में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक को शामिल करने या उसे अलग रखने का अधिकार है। इस मामले में आयातों की प्रकृति और दोनों कम्पनियों को चलाए जाने के ढंग को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की परिभाषा में आई.एस.एस.ए.एल. को शामिल करने का निर्णय लिया है। जांच अवधि के दौरान हुए लगभग 80,000 मी. टन के कुल उत्पादन में से आईएसएसएल और इस्पात प्रोफाइल इंडिया लि. का हिस्सा घरेलू रूप से उत्पादित उक्त वस्तुओं का लगभग 49,000 मी. टन का बनता है और इससे याचिका दायर करने की स्थिति संबंधी शर्त पूरी हो जाती है।

## आयात की न्यूनतम मात्रा

28. आर्थिक मंत्रालय, यूक्रेन ने अपने द्वारा किए गए अनुरोधों में, यह एक मुद्दा उठाया है कि यूक्रेन के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जांच अवधि के दौरान यूक्रेन से इस उत्पाद का भारत को निर्यात होने का कोई साक्ष्य नहीं है। अपने अनुरोधों में घरेलू उद्योग ने यह बताया है कि उन्होंने याचिका में ही इस संबंध में विस्तृत सूचना दायर कर दी थी कि यूक्रेन से उक्त किस्मों के आयात 1739 मी.टन के हुए थे और जिनका हिस्सा भारत में संबद्ध किस्मों के हुए कुल आयातों का 5.68% बनता है। इसलिए, जांच अवधि में यूक्रेन से हुए आयात न्यूनतम सीमा से कम नहीं थे।

## प्राधिकारी द्वारा जाँच

29. जांच की शुरुआत के समय याचिकाकर्ताओं ने जांच के प्रयोजनार्थ संबद्ध देशों से हुए संबद्ध वस्तुओं के आयातकों के संबंध में प्रथम दृष्टयासाक्ष्य के रूप में द्वितीयक स्रोतों से साक्ष्य

प्रस्तुत किए थे । तथापि, पाटनरोधी शुल्क लगाने के उद्देश्य से इस साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए इसकी किसी और प्रमाणिक साक्ष्य द्वारा पुष्टि की जानी आवश्यक है । डी.जी.सी.आई.एस. अथवा सीमाशुल्क प्राधिकारियों से सूचना के अभाव में क्योंकि बार, बिलैट्स तथा राऊंड्स के आयातों के ग्रेड-वार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं; निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत के समय प्रस्तुत सूचना के सत्यापन के प्रयोजनार्थ उन निर्यातकों तथा आयातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर भरोसा करने का निर्णय लिया है, जिन्होंने जांच में सहयोग दिया है । आयातकों द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर उक्रेन से हुए आयातों की सूचना के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है और चूंकि प्रारम्भिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ उक्रेन के किसी भी निर्यातक ने भाग नहीं लिया इसलिए उक्रेन से आयातों को शून्य और इस प्रकार उन्हें न्यूनतम मानने का निर्णय लिया गया है ।

**ज. पाटन तथा प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत के संबंध में किए गए दावों की जांच**

**30.** धारा-9 क(1) (ग) के अंतर्गत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

(1) समान वस्तु के लिए व्यापार के सामान्य रूप में तुलनीय मूल्य जब वह निर्यातक देश या क्षेत्र में उपयोग के निमित्त हो जिसका निर्धारण उप-धारा (6) के अंतर्गत नियमों के अनुसार किया गया हो; या

(11) जब व्यापार के सामान्य रूप में निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में समान वस्तु की बिक्री न हो या जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में विशेष बाजार स्थिति या बिक्री की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्री से उचित तुलना नहीं की जा सकती, तब सामान्य मूल्य इनमें से कोई एक होगा -

(क) समान वस्तु का तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य जब उसका निर्यात निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उपयुक्त तीसरे देश से किया जाए जिसका निर्धारण उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया गया हो; या

(ख) उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत; जिसमें प्रशासनिक बिक्री और सामान्य लागत तथा लाभ के लिए उपयुक्त राशि जोड़ी गई हो जिसका निर्धारण उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया गया हो;

बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से इतर किसी देश से किया गया हो तब जहां वस्तु को निर्यात वाले देश से होकर केवल वाहनान्तरित किया गया हो या ऐसी वस्तु का निर्यात वाले देश में उत्पादन नहीं किया जाता हो या निर्यात वाले देश में कोई भी तुलनात्मक कीमत नहीं हो तब सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में इसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा ।

31. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी थी। रूस के केवल एक निर्यातक मै. आस्कल इलैक्ट्रोमेटालर्जिकल कम्बिनेट ने निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत की थी। कम्पनी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, कम्पनी संबद्ध सामान को घरेलू बाजार में बेचकर तथा भारत में निर्यात करके दोनों तरीके से लाभ अर्जित करती है। उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, कुछेक ग्रेडों को उन कीमतों से कम मूल्य पर भारत को निर्यात किया जा रहा है जिन कीमतों पर सदृश ग्रेड घरेलू बाजार में बेचे जा रहे हैं। निर्यातक द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर, सामान्य मूल्य का आकलन किया गया है तथा पैकिंग, स्वदेशी भाड़े, बीमा इत्यादि के रूप में दावा किए गए समायोजनों की दावों के अनुसार अनुमति प्रदान की गई है। भारत को किए गए निर्यातों के संबंध में पैकिंग, स्वदेशी भाड़ा तथा अन्य खर्चों के लिए समायोजनों का दावा किया गया है। दावे के अनुसार अनुमति भी प्रदान की गई है। उपरोक्तानुसार की गई गणना के आधार पर पाटन मार्जिन निकाला गया है।

32. रूस के किसी अन्य विनिर्माता ने निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत नहीं की है तथा चीन एवं उक्रेन के निर्यातकों/विनिर्माताओं से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि सामान्य मूल्य के संबंध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर इन देशों में सामान्य मूल्य निकालने के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना पर विचार किया है। जहां तक निर्यात कीमत का संबंध है, संबद्ध वस्तुओं के आयातकों द्वारा दायर किए गए उत्तरों के आधार पर उपलब्ध सूचना का आवश्यक समायोजनों के पश्चात कारखाना स्तर पर निर्यात कीमत निकालने के लिए इस्तेमाल किया गया है।

### 33. नए निर्यातक

कुछ निर्यातकों/विनिर्माताओं ने दावा किया है कि जांच अवधि के दौरान उन्होंने भारत को निर्यात नहीं किया है। उपरोक्त पाटनरोधी नियमों के नियम-22 के अंतर्गत नए निर्यातक के रूप में इन निर्यातकों को जब भी वे भारत को निर्यात करते हैं समीक्षा हेतु आवेदन करने हेतु अनुमति प्रदान करने की परम्परा रही है।

### 34. पाटन मार्जिन

सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पादों के लिए संबद्ध देशों के मामले में प्रतिशत के रूप में (निर्यात कीमत एवं समायोजनों के पश्चात उसके % के रूप में) निम्नानुसार पाटन मार्जिन निकाला है:

देश एवं निर्यातक	पाटन मार्जिन
<b>रूस</b>	
(I) मै. आस्कल इलैक्ट्रोमेटालर्जिकल कोम्बिनेट	10.37
(II) अन्य निर्यातक	73.86
<b>चीन</b>	
सभी निर्यातक	105.12

### झ. क्षति

35. ऊपर नियम-11 अनुबंध-11 के अन्तर्गत जब क्षति का निष्कर्ष निकाला जाता है तो ऐसे निष्कर्ष में घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का निर्धारण भी शामिल होगा। ऐसा "करते समय सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा, जिनमें शामिल हैं-पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमतों पर उनका प्रभाव तथा ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का परिणामी प्रभाव"। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात की जाँच करना आवश्यक समझा गया है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में डम्प पाटित आयातों से कीमतों में पर्याप्त गिरावट आई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में कीमतों को अन्यथा कम करना या कीमतों में होने वाली वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी बढ़ गई होती।

36. उपर्युक्त नियम 11 के अंतर्गत अनुबंध-11 (iii) में यह व्यवस्था है कि "जिस मामले में किसी उत्पाद का आयात एक से अधिक देशों से हुआ हो और उनकी एक साथ पाटनरोधी जाँच हो रही हो तो निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से मूल्यांकन केवल तब करेगा जब वह यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक देश से किए गए आयातों के बारे में स्थापित डंपिंग मार्जिन निर्यात मूल्य के रूप में दिए गए 2 प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से किए गए आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयातों का 3% है अथवा जहां प्रत्येक देश का निर्यात 3 % से कम है वहां संचयी रूप से आयात समान वस्तु के आयातों का 7% से अधिक बनता है; और आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए आयातों की मात्रा एवं डम्पिंग मार्जिन उक्त निर्धारित सीमा से अधिक है।

37. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रूस तथा चीन से हुए आयातों के पाटन का मार्जिन तथा उसकी मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक है। आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करना उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से हुए निर्यात की कीमतें भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित कीमतों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा कर रही थी।

38. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों से पड़ने वाले प्रभाव की जाँच करने के लिए प्राधिकारी ने ऊपर नियमों के अनुबंध-11 (iv) के अनुसार ऐसे सूचकों पर विचार किया है जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जैसे उत्पादन, क्षमता-उपयोग, बिक्री की मात्रा, लाभप्रदता, कुल बिक्री प्राप्ति, डम्पिंग मात्रा और मार्जिन आदि।

**आयातों की मात्रा मी.टन में**

	रूस	चीन	यूक्रेन	अन्य	कुल
1997	22640	1248	0	154	27042
1998	31608	3912	3016	4456	42992
जांच अवधि (नौ महीने)	34918	3155	0	1587	39660

संबद्ध देशों से हुए आयातों की मात्रा 1997 में लगभग 24000 मी.टन से निरंतर बढ़ती हुई जांच अवधि के नौ महीनों में 38000 मी.टन हो गई है ।

**39. घरेलू उद्योग का उत्पादन निम्नानुसार रहा है:-**

उत्पादक	1996-97	1997-98	1998*	1999**
इस्पात प्रोफाइल (इ) लि.	26025.88	34042.72	28969.66	16865.18
आई एस एस ए एल	33485.00	66620.00	44373.53	32125.47
कुल	59510.88	80662.72	73343.19	48990.7

\* अप्रैल-दिसम्बर, 98

\*\* जनवरी-सितम्बर, 99

उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि में रहे उत्पादन स्तर की तुलना में अत्यधिक गिरावट आई है ।

**40. निर्यात कीमत**

हालांकि आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है तथापि संबद्ध देशों से हुए निर्यात की कीमत और पहुँच मूल्य में निरंतर गिरावट आई है । 1998-99 के बीच रूस से हुए आयात की औसत कीमत 15 207 रुपये प्रति मी.टन से घटकर जांच अवधि के दौरान लगभग 11000 रुपये प्रति मी.टन हो गई और चीन से हुए आयात की कीमत 13,770 रुपये से घटकर 9388 रुपये प्रति मी.टन हो गई। आयात कीमत में आई इस गिरावट से घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमत कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा जिससे उनकी बिक्री प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

**41. क्षमता उपयोग**

याचिकाकर्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया है और जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सत्यापित भी किया गया है कि इन सुविधाओं का इस्तेमाल संबद्ध प्रकार के ग्रेड सहित विभिन्न ग्रेडों के अलाय और गैर-अलाय इस्पात के बिलेट्स, बार्स और राउंड्स के उत्पादन हेतु किया जाता है जिसके लिए यह जांच की जा रही है । ऑर्डरों के अभाव में कंपनियों ने संयंत्र का इस्तेमाल दूसरे प्रकार के

बिलेट्स, बार्स और राउंड्स के उत्पादन के लिए करने का प्रयास किया। तथापि, संबद्ध प्रकार के बिलेट्स, बार्स और राउंड्स के उत्पादन से संयंत्र के बेहतर उपयोग और उत्पादन की उच्च मात्रा को सुनिश्चित करना समझा जाता है और संबद्ध वस्तुओं की मांग के अभाव में याचिकाकर्त्ताओं को संबद्ध ग्रेडों के उत्पादन को कम करना पड़ा।

#### 42. लाभ एवं हानि

आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की कीमत से काफी कम थी और यह उत्पादन लागत से भी कम थी जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की कीमत में कमी और बिक्री प्राप्ति में कमी आई है। इन कारकों की वजह से मै0 इस्पात प्रोफाइल इंडिया और मै0 आई एस एस ए एल दोनों को घाटा हुआ है।

#### 43. क्षति संबंधी निष्कर्ष

पूर्वोक्त से घरेलू उद्योग द्वारा क्षति के संबंध में किए गए निम्नलिखित दावों की पुष्टि की जाती है:-

- (क) संबद्ध देशों से हुए संबद्ध वस्तुओं के आयातों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है;
- (ख) घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है;
- (ग) घरेलू उद्योग के संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में गिरावट आई है,
- (घ) घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में कमी आई है;
- (ङ) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में तेजी से गिरावट आई है;
- (च) आयातों से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में भारी कटौती हुई है,
- (छ) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में अत्यधिक कमी आई है।

अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

पूर्वोक्त से घरेलू उद्योग द्वारा जांच अवधि के दौरान क्षति के संबंध में किए गए दावों की पुष्टि की जाती है।

#### अ. कारणात्मक संबंध

44. कारणात्मक संबंध के बारे में याचिका का विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए तर्क निम्नानुसार हैं:-

- (क) घरेलू उद्योग ने रूस, चीन और यूक्रेन से होने वाले आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की मांग की है। तथापि, उनके द्वारा प्रस्तुत आयात संबंधी आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि कुल आयातों का 27 प्रतिशत आयात जापान से उन कीमतों पर किया गया है जो संबद्ध देशों की कीमतों से काफी कम हैं। वस्तुतः जापान के लिए सी आई एफ मूल्य रूस के सी आई एफ मूल्य का 55 प्रतिशत है।



(ख) इस अकाट्य साक्ष्य के प्रत्युत्तर में घरेलू उद्योग ने एक रोचक तर्क दिया है। उनका यह तर्क कि जापान से हुए संबद्ध आयातों से उन्हें नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि जिस ग्राहक ने जापान से इसका आयात किया है वह उनका ग्राहक नहीं है और इस प्रकार संबद्ध आयातों के परिणामस्वरूप उन्हें बाजार का नुकसान नहीं हुआ है तथा क्षति संबंधी विश्लेषण स्वयं उन पर निर्भर करता है। यह जांच एक खास उत्पाद के खिलाफ है और यह उक्त उत्पाद के अंतिम उपयोग पर अथवा उसके ग्राहकों पर आधारित नहीं है। यहाँ हमें एक ऐसी स्थिति मिलती है जहाँ किसी आम उत्पाद की जांच की मांग एक अंतिम उपयोग पर आधारित है और इससे भी ज्यादा वह उन लोगों के संबंध में है जो उसके ग्राहक हैं। किसी भी पाटनरोधी जाँच में क्षति के बारे में इस प्रकार का कोई विश्लेषण विश्व के किसी भी भाग में नहीं सुना गया है। प्राधिकारी को यह मूलभूत प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या कारणात्मक संबंध का विश्लेषण याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा निर्दिष्ट ढंग से किया जाना है। यदि आयात किसी असंबद्ध देश से काफी कम कीमत पर हुए होते तो यह नहीं सोचा जा सकता कि ऐसी किसी कीमत से घरेलू उत्पादों की कीमत में कटौती नहीं हुई होगी। यदि याचिकाकर्ता के इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाए तो रूस, चीन और यूक्रेन की उच्चतर कीमतों से याचिकाकर्ताओं की कीमतों में कटौती नहीं हो सकती। इस प्रकार कारणात्मक संबंध का स्पष्ट तौर पर अभाव है।

#### 45. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

दिए गए तर्क के उत्तर में यह तर्क दिया गया है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II(iii) के पैरा 3 में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देशों से हुए आयातों और उत्पादों की पाटनरोधी जाँच की जा रही हो तो निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक आयात के प्रभाव का संचयी आकलन करेगा यदि वह यह निर्धारण करता है कि:

(क) प्रत्येक देश से हुए आयातों के संबंध में प्रमाणित किया गया पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त 2 प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयातों का 3 प्रतिशत है अथवा जहाँ अलग-अलग देशों का निर्यात 3 प्रतिशत से कम है, आयातों का संचयी रूप से हिस्सा समान वस्तु के आयातों का 7 प्रतिशत से अधिक है, और

(ख) आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करना उचित है;

46. प्रत्येक देश से हुए पाटन के मार्जिन उपर निर्धारित सीमाओं से अधिक है। विभिन्न देशों से हुए आयातों की मात्रा निम्नानुसार रही है:-

देश	आयातों की मात्रा मी.टन में	कुल आयातों का हिस्सा
रूस	18859	60.97
चीन	1680	5.49
यूक्रेन	1739	5.68
संबद्ध देशों से भिन्न देश		
जापान	8515	27.85

47. उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक संबद्ध देश से हुए आयातों की मात्रा न्यूनतम सीमा से अधिक है। आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन करना उचित है, क्योंकि संबद्ध देशों से हुए आयातों की कीमतें भारत में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत कीमतों से सीधे प्रतिस्पर्द्धा करती है। अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी से संबद्ध देशों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संचयी आकलन करने का अनुरोध किया है।

#### 48. प्राधिकारी द्वारा जांच

यह परम्परा रही है कि उपरोक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार जांच की कार्यवाही के दौरान संबद्ध देशों से हुई क्षति का संचयी आकलन किया जाए। इस मामले में याचिका का विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षों का तर्क यह है कि जांचाधीन देशों में से एक देश क्षति नहीं पहुँचा रहा है क्योंकि उनकी कीमत जांचाधीन देशों की निर्यात कीमत से काफी कम है। तथापि, जापान से हुए निर्यातों से पहुँची क्षति की मौजूदगी से यह अर्थ नहीं निकलता है कि जांचाधीन देशों से हुए निर्यातों द्वारा कोई क्षति नहीं पहुँच सकती। यह उस स्थिति में और अधिक प्रमाणित हो जाता है, जब संबद्ध देशों से हुए निर्यातों का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की उचित बिक्री कीमत से कम होता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए याचिका का विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षों का यह तर्क निर्दिष्ट प्राधिकारी को स्वीकार्य नहीं है और उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट तौर पर यह पता चलता है कि संबद्ध देशों से हुए पाटन और घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के बीच कारणात्मक संबंध है।

#### (ट) भारतीय उद्योग का हित तथा अन्य मुद्दे

49. आमतौर पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रयोजन पाटन को समाप्त करने से है जो घरेलू उद्योग की क्षति का कारण हैं और भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्द्धा स्थिति की पुनर्स्थापना करना है जो कि देश के आमहित में है।

50. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबंधित माल का उपयोग करते हुए विनिर्मित उत्पादों के मूल्य स्तर प्रभावित हो सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप इन उत्पादों की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर इसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है, परंतु भारतीय बाजार उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी साधनों से कम नहीं होगी, खासकर यदि पाटनरोधी शुल्क की लेवी को घरेलू उद्योग क्षति-पूर्ति के लिए एक आवश्यक धनराशि तक सीमित कर दिया जाय । इसके विपरीत पाटनरोधी उपायों को लागू करने से पाटन की क्रियाओं से उठाए जाने वाले अनुचित फायदे समाप्त हो जाएंगे, इससे घरेलू उद्योग की गिरावट रुकेगी और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं की व्यापक पसंद की उपलब्धता को बनाए रखने में मदद मिलेगी । पाटनरोधी उपायों को लागू करने से वस्तु देशों से होने वाले आयात किसी भी तरह सीमित नहीं होगा इसलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

### ठ. निष्कर्ष

51. पूर्वोक्त पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:-

- (क) रूस और चीन के निर्यातक सामान्य मूल्य से कम कीमत पर संबद्ध वस्तु का निर्यात कर रहे हैं जिससे पाटन हो रहा है;
- (ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;
- (ग) यह क्षति रूस और चीन से हुए पाटित आयातों द्वारा संचयी रूप से हुई है ।

संबद्ध वस्तुओं को आई एस विनिर्देशन अथवा आई एस मानकों के समतुल्य किसी अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशन के अनुरूप कुछेक ग्रेडों के अलाय और गैर अलाय इस्पात के ब्लेड्स छड़ियों और गोलियों के रूप में परिभाषित किया जाता है । कुछेक ग्रेडों की सूची उपरोक्त पैरा 7 में दी गई है ।

52. यह आवश्यक समझा गया है कि अंतिम निर्धारण होने तक रूस और चीन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित उपर दी गई संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए ।

53. इस प्रकार निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन और रूस से हुए संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अंतिम निर्धारण होने तक नीचे दी गई धनराशि के अनुसार, पाटन मार्जिन के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है ।

देश तथा निर्यातक	सिफारिश किए गए पाटनरोधी शुल्क (अमरीकी डालर प्रति मी.टन)
<u>रूस:</u>	
(i) मै0 आस्कल इलैक्ट्रोमेटालर्जिकल काम्बीनेट	16.03
(ii) अन्य निर्यातक	148.50
<u>चीन</u>	179.14

54. यह प्रस्ताव किया जाता है कि उपरोक्त पैरा 36 में उल्लिखित संबद्ध वस्तुओं पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए ।

**ड. आगे की प्रक्रिया**

55. प्रारंभिक निष्कर्षों को अधिसूचित करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी;

(क) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षों से इन निष्कर्षों के संबंध में टिप्पणियां आमंत्रित करेंगे और अंतिम निष्कर्षों में उन पर विचार किया जाएगा;

(ख) निर्यातकों, आयातकों, याचिकाकर्ताओं और संबंधित समझे जाने वाले अन्य हितबद्ध पक्षों को अलग से लिखा जा रहा है जो इस अधिसूचना के प्रेषण की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं । कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी इन निष्कर्षों के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकता है ।

(ग) अंतिम निष्कर्षों की घोषणा करने से पहले प्राधिकारी द्वारा आवश्यक तथ्यों को उजागर किया जाएगा ।

एल. बी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
**(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st December, 2000

**PRELIMINARY FINDINGS** ०

**Subject: Anti-dumping investigation concerning import into India of certain seamless grade alloy and non alloy steel billets, bars and rounds from Russia, China and Ukraine.**

**31/1/99-DGAD.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Custom Tariff (identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and For Determination of Injury) Rules, 1995, thereof:

**A. PROCEDURE**

1. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
  - (i) The Designated Authority (hereinafter also referred to as Authority), under the above Rules, received a written application from M/s. Ispat Profile India Limited and on behalf of domestic industry alleging dumping of certain seamless grade alloy and non alloy steel billets, bars and rounds from Russia, China and Ukraine (herein after also referred to as subject goods)

- originating in or exported from Russia, China and Ukraine (hereinafter referred to as subject countries);
- (ii) Preliminary scrutiny of the application filed by petitioners revealed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the petitioners. The petition was therefore considered as properly documented;
  - (iii) The Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the petitioner decided to initiate the investigations against import of the subject goods from the subject countries. The Authority notified the embassies of Russia, China and Ukraine about the receipt of application for dumping investigation before proceeding to initiate investigations in accordance with sub-rule 5(5) of the Rules;
  - (iv) The Authority issued a public notice dated 9<sup>th</sup> December 1999, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigations concerning imports of subject goods classified under custom code 7206.90, 7207.19 and 7207.20 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975 originating in or exported from subject countries. A corrigendum was also issued on 21.1.2000 making certain corrections in the list of grades subject to investigation;
  - (v) The Authority forwarded a copy of the public notices to all the known exporters (whose details were made available by the petitioners) and industry associations and gave them an opportunity to make their views known in writing in accordance with the rule 6(2);
  - (vi) The Embassies of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the investigation in accordance with rule 6(3) with a request to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter, petition and

- questionnaire sent to the exporters was also sent to their respective Embassies, along with a list of known exporters/producers;
- (vii) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers (whose details were made available by petitioner) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter. A copy of the petition was also provided to other interested parties.
  - (viii) Request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) & Director General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods made in India during the past three years, including the period of investigation.
  - (ix) The Authority conducted on-the-spot investigation at the premises of the petitioners to the extent considered necessary.
  - (x) Additional information regarding injury was sought from the petitioners, which was also furnished;
  - (xi) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties;
  - (xii) \*\*\*\*\*in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules;
  - (xiii) Investigation was carried out for the period starting from 1<sup>st</sup> January 1999 to 30<sup>th</sup> September 1999;
  - (xiv) Cost investigations were also conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the petitioners also so as to ascertain if anti-dumping duty lower

than dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry;

- (xv) The Authority sent a questionnaire, to elicit relevant information, to the following known exporters, in accordance with Rule 6(4);

1. Tianjin Pipe Corpn, PR China
2. Multiera Commodities Ltd., Ukraine
3. Chelia Binsk Tube Rolling Plant, Russia
4. Volski Tube Mill, Russia
5. Volski Tube Mills, Russia
6. Tyazhpromexport, Russia
7. Kuznetsky Met Kombinat, Pobedy
8. Magnitogorsky Met Kombinat, Kirova
9. Nizhnetagilsky Met Kombinat, Nizhny Tagil
10. Novolipetsky Met Kombinat
11. Cherepovetsky Met Kombinat, Mira
12. Azovstal Met Kombinat, Leporskogo
13. Serp 1 Molot, Zolotorozhsky Val
14. Dalnevostochny Rolled Steel Plant, Moscow

- (xvi) A questionnaire was sent to the following known importers calling for necessary information in accordance with rule 6(4);

1. Maharashtra Seamless Ltd., N Delhi
2. Kalyani Seamless Tubes Ltd., Pune



3. Indian Seamless Tubes Ltd., Pune
4. Bharat Heavy Electricals Ltd., Tiruchy
5. Association of Seamless Tube Mfrs., Pune

(xvii) Copies of initiation notice were also sent to :-

1. Assocham, N Delhi
2. CII, New Delhi
3. FICCI, N Delhi

(xvii) All interested parties were provided an opportunity to present their views on issues under consideration before Director (Anti Dumping) on 22.5.2000 and a public hearing was held under the chairmanship of Designated Authority on 16.10.2000.

**B. VIEWS OF PETITIONERS, IMPORTERS, EXPORTERS, EMBSSIES OF EXPORTING COUNTRIES AND OTHER INTERESTED PARTIES**

**2. PETITIONERS VIEW**

The petitioners, M/s. Ispat Profile India Limited, supported by M/s. Indian Seamless Alloys Limited filed petition on behalf of the domestic industry and raised the following major issues in their submissions:-

- (i) The petitioner had set up the plant for manufacture of alloy and non alloy steel of various grades and sizes with a manufacturing capacity of 2,50,000 tpa employing state-of-the-art technology of steel making and providing direct and indirect employment to over 2000 persons.
- (ii) They are currently the largest manufacturer of steel in various shapes and sizes and their product are not only marketed in domestic market but have also found favorable response from off shores. They have the reputation of 'zero' defective steel and have also earned ISO 9002 Certification. Their products are import substitute and help in saving valuable foreign exchange. Their exports are also bringing foreign exchange to the tune of Rs.15 crores per annum.
- (iii) Substantial part of their production have been traditionally going in for seamless tube grade – billets, bars and rounds. However, exporters from Russia, Ukraine and China resorted to severe price reduction in the Indian market in the past three years. The prices have been reduced from about US\$ 350 in 1996-97 to US\$ 260 in April December 1998. In fact the prices have already been reduced to the level of US\$ 209 pmt. Considering the expenses involved in export of goods to India, it is evident that the exporters are resorting to selling below variable cost of production. Evidently the goods are being dumped in the Indian market. This has severely affected these operations to such an extent that they hardly have any orders for seamless tube grades bars, billets, and rounds.
- (iv) ISPAT is a leading supplier in the country in this grade of material. ISSAL and Kalyani Steels Ltd., also produce these grades of material. Capacity is also coming up at Hospet. Though ISPAT is one the largest producer of seamless grades alloy and non alloy steel, yet other producers like ISSAL have supported the petition. Dumping from these countries have not only

materially injured the existing producers but also would result in material retardation to the establishment of new companies.

- (v) In view of severe dumping being faced in the country resulting in massive losses to ISPAT, they have requested for imposition of anti dumping duty on seamless grade alloy and non alloy steels.

### 3. **Views of Trade Representation of Russian Federation in India:**

- (i) First of all, there is some contradiction and inaccuracy in the definitions of the subject matter for investigation used in the petition and notification. There is no category as "certain seamless grade alloy and non alloy steel billets, bars, rounds" in Customs or in any other official statistics. Only definition like "billets, bars, rounds" can be referred to and verified and therefore be taken into account.
- (ii) Secondly, the list of Indian producers should incorporate not only four companies mentioned by the petitioner but all other producers like SAIL, ESSAR, JINDAL, TATA etc., and correspondingly total scope of their production must be taken into consideration. According to "Steel Scenario Statistical yearbook 1999", total production of billets, bars, rounds in India in 1998-99 was 12,466 thousand tonnes. They have further stated that the share of petitioner in total Indian production is much lower and therefore there is serious doubt about the validity of the application.
- (iii) As to the exports of the Russian origin, they in no way can affect the Indian domestic industry since exports of Russian origin as given in the petition and "Monthly Statistics of Foreign Trade in India" make up only 0.18% or 0.72% of the total Indian production as given in (ii) above. In view of the above there is

causal link between imports from Russia and alleged material injury to the domestic industry.

- (iv) In addition to the above, we have not found any reliable explanation to the fact that the imports from Japan were not taken into account though they were rather high and the average prices (which might be calculated using the data given in the petition) were almost half of the Russian average prices.
- (v) As to the actual Russian prices, it is very clearly seen from the break-down of the prices given in the answers of the "Oscol Electrometallurgical combinat" that they are not dumping prices.
- (vi) In view of the above we consider that in general, the investigation must be terminated due to lack of correct, objective and verified information for it. In any case, in particular, no anti dumping measures must be taken against the Russian producers.

**4. Views of Ministry of Economy of Ukraine**

- (a) There has been a violation of procedure of investigation as the complete description of product, information about prices, date of initiation of investigation and volume of allegedly dumped imports has not been given;
- (b) the petition does not contain sufficient information and evidence on the like product and the evidence on prices at which the product under investigation originating in Ukraine was sold in India;
- (c) it has also been argued that in accordance with the official Ukraine statistics, there is no evidence of export from Ukraine to India of the product during the period of investigation;

- (d) it is therefore requested to exclude Ukraine from the list of countries under investigation.

**5. Submissions by the importers, users and M/s. OEMK, a Russian exporter.**

Three core issues highlighted by the counsel for M/s. Maharashtra Seamless Ltd., and M/s. OEMK, Russia, are as follows:-

- (a) What is the product under investigation ? In other words, the product on which the anti dumping duty will be imposed (product under consideration)
- (b) For the products so identified does the petition specify the standing required under Rule 5(3) (a) ? (question of standing)
- (c) *Prima facie* is causal link attributable to the imports from Japan is attributed to the three countries subject to investigation ?

The submissions made on these issues have been discussed in detail at appropriate places in the findings below. Apart from the above, representations have been received from Federation of Engineering Industries of India, All India Steel Rollers Association, Prabhat Steel Traders, Eagle Steels etc., who are the users/importers of the specified grades of alloy/non alloy steel billets, bars and round, giving their comments on the issues highlighted above which are also dealt with below.

### C. EXAMINATION OF THE ISSUES RAISED

6. The submissions made by the petitioner, exporters and importers and other interested parties to the extent these are relevant as per Rules and to the extent these have a bearing upon the case have been examined and considered and have been dealt with at appropriate places in these findings.

### D. PRODUCT UNDER CONSIDERATION:

7. As per the description given in the Initiation Notification, the product involved in the investigation is "certain seamless grade alloy and non alloy steel billets, bars and rounds from Russia, China, Ukraine. " The product falls under custom sub-heading 7206.90, 7207.19 and 7207.20 of Customs Tariff Act, 1975 which are only indicative and not binding on the scope of the investigation. The grades of alloy and non alloy steel billets, bars and rounds subject to the investigation have been mentioned in the initiation notification and corrected by corrigendum dated 21.1.2000. These grades are -

S. No	I.S. SPECIFICATIONS	EQUIVALENT INTERNATIONAL SPECIFICATION
1	I.S. 1875,CL1	ASTM, SA192, AP15L Gr X 42
	(NON-ALLOY STEEL)	B53059PT – 2Gr 243, DIN, CK 15
2	I.S 1875, CL1A	SAE 1018, ASTMA 333
	(NON-ALLOY STEEL)	
3	I.S 1875, CL 2	SA 1026
	(NON-ALLOY STEEL)	
4.	I.S 1875, CL2A	ASTM, SA210A1,AP1 SLGrB

	(NON-ALLOY STEEL)	APISLGr X 46, APISL X -46
5	I.S. 1875, CL3	ASTM,SA210GrC, SAE1030
	(NON-ALLOY STEEL)	
6.	I.S 1875,CL3A	SAE140,SAE1035
	(NON-ALLOY STEEL)	
7.	I.S 1875,CL4	BS,En 8D.
	(Non-ALLOY STEEL)	
8.	I.S 1875,CL5	SAE 1050
	(NON-ALLOY STEEL)	
9.	I.S 5517, 27C15	SAE 1530
	(NON-ALLOY STEEL)	
10.	I.S 5517,37C15	BS, En15, SAE 1541
	(NON-ALLOY STEEL)	
11.	I.S 4432, 10C4	ASTM, SA 179, SAE 1010
	(NON-ALLOY STEEL)	SAE 1008
12.	I.S 4368, 20Mn2	DIN 2391 st 52, SAE 1518
	(NON-ALLOY STEEL)	
13.	I.S 5517, 35 Mn6Mo3	API N80, SAE 4042
	(NON-ALLOY STEEL)	
14.	I.S.EQUIVALENT NOT	SAE 4130
	AVAILABLE (ALLOY STEEL)	
15.	I.S.EQUIVALENT NOT	SAE 4118 (Nearest)
	AVAILABLE (ALLOY STEEL)	
16.	I.S. EQUIVALENT NOT	BS 3602 Pt 1500 Nb
	AVAILABLE (ALLOY STEEL)	(Microalloyed Steel)
17.	I.S.EQUIVALENT NOT	BS 3059 PIII Gr 440

	AVAILABLE (NON ALLOY STEEL)	
18.	I.S. EQUIVALENT NOT	SAE 1518
	AVAILABLE(NON-ALLOY STEEL)	
19.	I.S 4398, 103 Cr 2,	SAE 52100
	(ALLOY STEEL)	
20.	IS 4368 20 Mn Cr 1	20 MNCRS
21.	IS 3749 T 105 Cr 5	
22.	IS 3930 40 Cr4 Mo 3	
23.	IS 4368 21 Cr 1 Mo 28	
24.	IS 5517 27 CL 5 + MO	
25.	IS 4432 CLO	MSL 4A
26.	IS 5517 37 CL 5	
27.	IS 4368 37 SI 2 Mn 90	
28.	IS 5517 3795 37 CL 5 + Mo	
29.	IS 4368 40 NI 2 Cr 1 Mo 28	

Arguments raised by various interested parties on this issue are as follows:

8. **Arguments raised by importers and exporters:** In their reply to the initiation notification and questionnaire, the following arguments were given by the Counsel for importers and exporters:

- (a) As per part I of the non confidential version of the petition the product alleged to be dumped is certain grade alloy and non alloy steel billets, bars, rounds having 70mm to 250 mm dia. It is further stated in the petition that the subject goods have a large number of applications. It



has been added that the subject goods are primarily and largely used in production of seamless tubes. It has also been indicated that the said grades are used for manufacturing of seamless tubes/pipes, as also for some forging applications and that they are primarily used for production of seamless tubes/pipes. It is thus seen from the petitioner's plea that the billets, bars and rounds of said size are used in the manufacture of seamless tubes/pipes as also in other applications. The petitioners have nowhere used the term 'seamless grade'.

- (b) The initiation notice dated 9.12.99, however, describes in para 2, the product involved as 'certain seamless grade alloy and non alloy steel billets, bars, rounds originating in or exported from Russia, China and Ukraine". The initiation notice had introduced the words 'certain seamless grade' which are not appearing in the petition. Likewise the diameter of the subject goods, mentioned in the petition as 70mm to 250 mm, has been omitted in the initiation notice. The scope of the product under consideration has been widened by the Authority. The initiation is bad on this count alone.
- (c) Regarding the product's specification, the question whether there is a category called certain seamless grade alloy and non alloy steel billets, bars, rounds at all has to be addressed. The petitioner have referred to various grades such as IS 1875, IS 3749, IS 3940, IS 5517, IS 4432 and IS 4368 as the specification of products. The technical literature available shows that these grades are used for forging for making tools and dies and for general engineering purposes. Some of these grades referred to the specification for steels are for hardening and tempering. Therefore, it is quite clear that these grades

have many applications other than merely for seamless tube making as specified by the petitioners in the non confidential version of the petition.

- (d) Anti dumping duty cannot be end use based as the objective of the petitioner seems to be to get the duty imposed only on the import of specified grades by the seamless tube manufacturers. Further the investigation will result in a situation where each consignment of billets, bars and rounds imported from the subject countries has to be held up by the Customs in order to perform tests to determine whether the item falls under one of the types subject to anti dumping duty resulting in absolute chaos. The anti dumping duty cannot be recommended on billets, bars and rounds as the investigation is on specific grades only and because the importer and users for other purposes of the subject goods have not been involved in this investigation. The action of the petitioners in selecting certain grades that are not meant exclusively for seamless application is *malafide* and if the Authority conducts the investigation on such basis and recommends levy of anti dumping duty on the grounds without any reference to their end use it would amount to imposing duty on the said grades meant for other applications. Such an action is violative inasmuch as other users of the said grade have not been notified. Similarly all producers of billets/rounds of the said grades other than the petitioner, especially the integrated steel producers have not been considered. If their production is considered the standing requirements under Rule 5(3A) will not be met by the present petitioner. If on the other hand the duty is sought to be levied on the said grades alone based on the end use, such a

recommendation is not capable of being implemented by Customs apart from being contrary to the CEGAT finding in the 'catalyst case'.

- (e) Apart from this, representation made by Federation of Engineering Industries, Prabhat Steel Traders, Eagle Steels and All India Steel Re-rollers Association have also emphasized the alternative uses of the specified grades for purposes other than making of seamless pipes/tubes and questioned the standing of the petitioners on account of there being other producers supplying to users other than seamless tube manufacturers.

9. **Submissions by domestic industry:** In their submissions in reply to the points made by the other interested parties, the petitioners have stated that in their request for imposition of anti dumping duty, product under consideration mentioned by them is as follows:-

*" The name of the product being dumped in India is certain types of alloy and non alloy steels bars, billets and rounds having 70 mm to 250 mm dia, conforming to IS specifications or any other international specifications equivalent to the IS standards. List of the IS specifications and chemical compositions is enclosed with this petition."*

10. It is submitted that while quoting the initiation notification issued by the Designated Authority the opposing interested parties have read only the first line of the description and they have ignored the second line which makes description very clear. The initiation notice reads as –

*The product involved in the investigation is certain seamless grade alloy and non alloy steel billets, bars and rounds originating in or exported from Russia, China and Ukraine. The petitioners have sought imposition of anti dumping duty only on the following grades of alloy and non alloy steel billets, bars and rounds."*

11. Though Maharashtra Seamless Ltd., had argued that subject goods have a very wide application and have attempted to give an impression as if the subject goods are consumed in large volume by a large number of companies, the fact is that except seamless pipe producers, no other party bothered to provide necessary information to the Authority and represent its interests. At the time of hearing they had specifically desired from the representatives of the Federation of Engineering Industries that the details with regard to consumers of the subject goods, their annual requirements and their three year purchase of the subject goods from domestic sources and imports may be provided to the Authority to establish that there are other interested parties who consume this material in substantial volumes. It is submitted that such information is not forthcoming from these parties even to date.

12. The submissions made by the importers and the response filed by the exporter M/s. OEMK, Russia, clearly shows that they have understood the product as being used mainly for manufacture of seamless tube, pipes, which is understood to be seamless grade. The question whether the subject goods are primarily and largely used for production of seamless tube is a question of fact. The fact on record shows that almost entire demand of the subject goods is from those producers who have purchased these for manufacture of seamless tubes. Further the companies

whose production and sales information has been provided by us represents a significant proportion of the producers of the subject goods.

13. The objection of the Maharashtra Seamless Ltd., is that the action of the Designated Authority in both widening the scope in respect of size and restricting the scope based on end use is unwarranted. Since the objection is only with regard to the scope of investigations, the same can always be suitably modified by the DA while recording findings. In fact, it is the duty of the DA under the law to investigate the scope of proposed anti dumping duty for conducting due investigations. While the scope can always be restricted in subsequent investigation, the same cannot be widened. The scope can thus be restricted to those areas for which we have sought duty. It is submitted that any modification in the product description does not mean a modification in the product under consideration.

14. It is submitted that the opposing interested parties have been very strongly arguing that seamless making is not even mentioned in the IS specifications given in the petition. We submit in this connection that seamless making is nothing but a forging application.

15. It has been argued that the Central Government would not be in a position to impose the duty in case it is recommended and it would result in undue hardship to the consumers. In this context it is submitted that the effect of imposition of anti dumping duty is differential duty on the same product depending on the source. Implementation of the orders of DA by the Central Government in other cases suggest that even in this case there should not be any problem in implementing the order imposing anti dumping duty. Assuming, though not admitting there will be some difficulties in implementation of the duties, it does not imply that the domestic

industry should be deprived of its legitimate rights to seek protection under the Rules. The domestic industry is committed to supply the goods to the consumers at competitive prices.

16. It has been argued that the product under consideration cannot be described based on end use and duties imposed accordingly. It is submitted that the product is described in terms of a number of important characteristics which a product is considered to possess and one of these characteristics is its uses. So describing the product by the use it is put to, does not imply that the duty is being sought on that particular end use only.

#### **17. Examination by Authority**

The Authority accepts the argument made by the domestic industry regarding the definition and description of the product given above. Apart from giving the description of the product, the Authority had mentioned specifically the grades on which the antidumping duty was sought to be imposed by the petitioner which should have eliminated the confusion projected to have been created by the word "seamless" grade in the Initiation notification. However, the thickness of the billets, bars and rounds on which duty was sought to be imposed was omitted inadvertently. While accepting the contention of the domestic industry the DA has decided to amend the description of the product as "certain types/grades of alloy and non alloy steel billets, bars and rounds having 70 mm to 250 mm diameter conforming to IS specification or any other international specification equivalent to IS standards". These grades are mentioned in paragraph 7 above. Hence, the DA also restricts the investigation to the sizes 70-250 mm dia. The list of grades as mentioned in the initiation notification dated 9.12.99 and corrigendum dated

21.1.2000 remains the same and the findings are being issued accordingly. Here it may be mentioned that it is only the certain grades which have been specified in paragraph 7 are the subject goods under investigation and not all the grades of alloy and non alloy steel billets, bars and rounds as has been made out by the importers and Trade Representation of the Russian Federation.

#### **E. Like Article**

18. The petitioner has claimed that the subject goods produced by the domestic industry has characteristics closely resembling to the goods being imported from the subject countries. Further the petitioners have claimed that the goods produced by domestic industry and imported from subject countries have to conform to certain given technical specifications laid down by the consumers and the goods are in fact identical in nature.

19. It has been further argued by the opposing interested parties that the DA is adopting a inconsistent stand in initiating the investigation. It has been argued that in the anti dumping investigation on seamless tubes/pipes, the Authority initiated investigation and published the preliminary finding discarding the arguments that casing, tube and line pipes are for specific end use and cannot be substituted. The view of the Authority is that there is such a thing as seamless grade billets, bars and rounds and as such they can be used only for making seamless tubes which is factually incorrect as demonstrated supra. If this argument is correct then casing/production/line pipes for specific end use cannot be treated as a single product. The DA cannot be correct in both the cases.

**20. Examination by Authority**

In the case relating to the anti dumping investigation against imports of seamless tubes/pipes, it may be mentioned that there are separate custom classification nos. 7304.10, 7304.29 and 7304.39 respectively for line pipe, casing pipe and boiler pipe. This clearly shows that these pipes are defined separately in terms of various characteristics and at the time of import, a separate custom sub heading is to be mentioned. Separate duties have been recommended on these distinct custom classifications in the findings considering that these are different types of seamless tubes/pipes.

21. The aforesaid modification in the description of the product, (by dropping the word 'seamless') as carried out by the Authority renders the point made by the importers redundant. Also it was never the argument of the DA that the specified grades of the subject goods are used for making seamless tubes only. In view of above, the DA is convinced that product under consideration being sold by the domestic industry are 'like article' to the subject goods being imported from the subject countries within the meaning of said Rules.

**F. DOMESTIC INDUSTRY, RELATIONSHIP AND STANDING OF PETITIONER AND SUPPORTER**

22. Rule 5(3) of the Anti Dumping Rules requires –

“ The DA shall not initiate an investigation pursuant to an application made under sub rule (1) unless –



“ (a) *it determines, on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to the application expressed by domestic producers of the like product, that the application has been made by or on behalf of the domestic industry:*

*Provided that no investigation shall be initiated if domestic producers expressly supporting the application account for less than 25% of the total production of the like article by the domestic industry and.....;*

*Explanation:- For the purpose of this rule the application shall be deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry, if it is supported by those domestic producers whose collective output constitute more than 50 per cent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition as the case may be, to the application.”*

### **23. Standing and Relationship**

It has been argued by interested parties opposing the petition that as per Rule 2(b) of the Anti Dumping Rules, the domestic industry has been defined to include all the domestic producers engaged in the manufacture of like article. However, the producers were related to importers of allegedly dumped articles and may be excluded. It is further submitted that the supporter of the petition M/s. Indian Seamless Steel and Alloys Ltd., (ISSAL) is related to Indian Seamless Metal Tube Ltd., (ISMT) who have imported the subject goods during the period of investigation. It is further stated that M/s. ISSAL and ISMT have common chairman and three common directors and also ISTL holds shares worth Rs.1.1 crore in ISSAL.

24. It has further been argued by the opposing interested parties that there are producers of billets, bars and rounds other than the ones mentioned by the petitioners in the petition. If all the grades of billets, bars and rounds produced in the country are taken then in the year 1998-99 approximately 7.5 million MTS of billets have been produced and the production by the petitioner and the supporter is a miniscule 2 per cent of the total domestic production which will imply that they do not have the standing to file the petition. It has further been argued that even the grades mentioned in the petition have been produced by SAIL and Mahindra Ugine Steel Co. Ltd., (MUSCO) during the period of investigation. M/s. Maharashtra Seamless Ltd., have purchased 346 MTS and 278 MTS of subject goods from SAIL and MUSCO respectively during the period of investigation..

25. On the basis of the arguments mentioned above, the interested opposing parties have contended that the petitioner and the supporters do not have any *locus standi* to represent the domestic industry and the investigation should be terminated accordingly.

**26. Examination by Authority**

The Designated Authority, before initiating the investigation and also after the submissions were made by the interested opposing parties, contacted various Govt. agencies dealing with steel industry and major producers of steel in India to find out the status of domestic industry for the subject grades. In their replies it has been stated that a subsidiary company of SAIL, produced 1132 MTS of said grades in 1998-99 and no information was available regarding the producers other than those

stated in the petition. Therefore, on the basis of the information available, there is no evidence of the production of certain grades of alloy and non alloy bars, billets and rounds specified in the petition being significantly more than the production mentioned in the petition. While addressing the question of 'standing', existence of production capacity *per se* is not relevant. The 'standing' is to be determined on the basis of evidence regarding the share of the petitioners and supporters in actual production of subject goods by the 'domestic industry'.

27. Regarding the question of relationship, the interested parties opposing the petition have raised the issue of ISSAL being related to ISMT who are the importers of the said grades. On verification it was found that the imports by ISMT are under the Duty Exemption Scheme and hence these have not entered the commerce of the country as these imports go into the export production. *Vide* the amendment dated 15<sup>th</sup> July 1999 to the Anti Dumping Rules, the DA has the discretion to include or exclude an importer of the subject goods from the definition of domestic industry. In this case in view of the aforesaid nature of the imports, the DA is inclined to include ISSAL in the scope of domestic industry. Out of total production of approximately 80000 MTS during the investigation period, both ISSAL and Ispat Profile India Limited accounted for approximately 49000 MTS of the said goods produced domestically and this satisfies the condition of standing to file the petition. Here again it needs to be mentioned that it is only the total production of the specified grades mentioned in paragraph 7 which has been taken into account for the purpose of determining the stand of the petitioner and the supporter to file the petition for anti dumping investigation and not the total production of alloy and non alloy steel billets, bars and rounds. It is only the specified grades which fall within the definition of product under consideration and not all grades of alloy and non alloy steel billets, bars and rounds.

**DEMINIMUS VOLUME OF IMPORT**

28. In their submissions made, the Ministry of Economy, Ukraine had made a point that in accordance with the official Ukraine statistics there is no evidence of export from Ukraine to India of the product during the investigation period. In their submissions the domestic industry has stated that they had filed detailed information in the petition itself that the imports of the said types from Ukraine were 1739 MTS and constitute 5.68% of the total imports of the subject types in India. The imports from Ukraine were therefore not *deminimus* in the investigation period.

**Examination by Authority**

29. At the time of initiation of investigation the petitioners had given evidence from secondary sources regarding the imports of subject goods from the subject countries as a *prima facie* evidence for the purpose of initiation. However, this evidence needs to be corroborated by some more authentic evidence for being accepted for the purpose of levying anti dumping duty. In the absence of information from DGCIS or Custom authorities as the records are not maintained on imports of bars, billets and rounds grade-wise, the DA decided to rely on the evidence furnished by the exporters and importers who have cooperated in the investigation for the purpose of verification of information submitted at the time of initiation. There is no evidence of information on imports having taken place from Ukraine on the basis of the submissions made by the importers and as no exporters participated from Ukraine, for the purpose of preliminary finding it has been decided to take the imports from Ukraine as nil and therefore, *deminimus*.

## H. DUMPING & EXAMINATION OF CLAIMS ON NORMAL VALUE & EXPORT PRICES BY THE AUTHORITY:

30. Under Section 9A(1)©, normal value in relation to an article means:

- (i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section(6); or
- (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either -
  - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
  - (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is

no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

31. Authority sent questionnaires to the exporters from the subject countries. Only one exporter from Russia M/s. Oskol Electrometallurgical Combinat (OEMK) furnished the information in the prescribed format. As per the information furnished by the company the company makes profit selling the subject goods both in the domestic market and on exports to India. As per information furnished, some of the grades are being exported to India at the price below for which analog grades are being sold in the domestic market. Normal value has been worked out on the basis of the information provided by the exporter and adjustments claimed in the form of packing, inland freight, insurance etc., have been allowed as claimed. On the exports to India also, the adjustments have been claimed for packing, inland, freight and other expenses which also has been allowed as claimed. The dumping margin has been worked out on the basis of calculations made above.

32. None of the other manufacturers in Russia has supplied information in the prescribed format and also no reply has been received from the exporters/manufacturers from China and Ukraine. As no information on normal value has been furnished, the DA has considered the information provided by petitioners for the purpose of arriving at normal value in these countries on the basis of constructed cost of production. Regarding the export price, the information available on the basis of replies filed by importers of the subject goods has been used for arriving at the export price at ex-factory level after making necessary adjustments.

**33. New exporters**

Some of the exporters/manufacturers have claimed that they have not exported to India during the period of investigations. It has been the practice to allow these exporters to apply for review as new exporter under Rule 22 of Anti-Dumping Rules mentioned above as and when they export to India.

**34. Dumping Margins:**

On the basis of the best information available, the Authority has arrived at the dumping margins in percentage terms (as percentage of export price after adjustments) in the case of subject countries for products under considerations is as follows:

Country and exporter	Dumping margin
<b><u>Russia</u></b>	
(i) M/s. Oskol Electrometallurgical Combinat (OEMK)	10.37
(ii) Other exporters	73.86
<b><u>China</u></b>	
All exporters	105.12

**I. INJURY**

35. Under rule 11 *supra*, when a finding of injury is arrived at, such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry. "taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on

domestic producers of such article.....” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

36. Annexure II (iii) under Rule 11 *supra* further provides that “in cases where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to Anti dumping investigation, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, only when it determines that the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the imports of the like article or where the export of the individual countries less than three percent, the imports cumulatively accounts for more than seven percent of the imports of like article, and cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

37. The Authority notes that the margin of dumping and quantum of imports from Russia and China are more than the limits prescribed above. Cumulative assessment of the effects of imports are appropriate since the export prices from the subject countries were directly competing with the prices offered by the domestic industry in the Indian market.

38. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such further indices having a bearing on the state of the



industry as production, capacity utilization, sales quantum, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II (iv) of the rules *supra*.

**Volume of Imports in MTS**

	<b>Russia</b>	<b>China</b>	<b>Ukraine</b>	<b>Others</b>	<b>Total</b>
1997	22640	1248	0	154	27042
1998	31608	3912	3016	4456	42992
POI (nine months)	34918	3155	0	1587	39660

The volume of imports from subject countries has increased steadily from approximately 24000 MTS in 1997 to 38,000 MTS in nine months of Pol.

39. The production of the domestic industry has been as under:

**in MT**

Producer	1996-97	1997-98	1998*	1999**
Ispat Profile (I) Ltd	26025.88	34042.72	28969.66	16865.18
ISSAL	33485.00	46620.00	44373.53	32125.47
Total	59510.88	80662.72	73343.19	48990.7

\* April-Dec'98

\*\* Jan-Sept'99

From the above it is clear that the domestic industry's production has declined as compared with the production level in the comparable period last year.

**40. Export Price**

While the imports volume has increased there has been a steady fall in the export price and the landed value from the subject countries. Between 1998 and 1999 the average price of import from Russia fell from Rs.15207 PMT to approximately Rs.11,000 PMT during investigation period and that from China it fell from Rs. 13,770 to Rs.9388 PMT. This fall in the import price has forced the domestic industry to reduce its sale price adversely affecting their sales realisation.

**41. Utilisation of capacity**

It has been submitted by the petitioner and also verified by DA that the same facilities are used for production of various grades of alloy and non alloy steel billets, bars and rounds including the subject types for which this investigation is being conducted. In case of absence of orders the companies attempts to utilise the plant by producing other types of billets, bars and rounds. However, production of subject types of billets, bars and rounds is supposed to ensure better plant utilisation and higher production volume and in the absence of demand for the subject goods, the petitioners had to cut down the production of subject grades which also adversely effected their capacity utilisation.

**42. Profit & Loss**

The landed price of imports is considerably below the fair selling price of the domestic industry and much below the cost of production resulting in price

suppression and lower sales realisation for the domestic industry. Because of these factors, both M/s. Ispat Profit India and M/s. ISSAL have been incurring losses.

**43. Conclusions on Injury:**

From the foregoing the following claims made regarding injury by the domestic industry are confirmed:

- (a) Imports of subject goods from the subject countries have increased in absolute terms;
- (b) The market share of the domestic industry has declined;
- (c) Production of subject goods of the domestic industry has declined;
- (d) Capacity utilization of the domestic industry has declined;
- (e) Sales in absolute volume & value terms of the domestic industry have declined;
- (f) Selling prices of the domestic industry have declined steeply;
- (g) Imports are significantly undercutting the selling prices of the domestic industry;
- (h) The profitability of the domestic industry has been severely eroded.

The Authority therefore concludes that the domestic industry has suffered material injury and the claims made regarding injury during the period investigation by domestic industry are confirmed.

**J. CAUSAL LINK**

44. The arguments made by the interested parties opposing the petition regarding the causal link are as follows:-

- (a) The domestic industry has sought anti dumping duties in respect of imports emanating from Russia, China and Ukraine. However, from the import data furnished by them, it is clear that 27% of the total imports are from Japan at prices which are far lower than the prices of the subject countries. In fact, the cif value for Japan is 55% of the cif value from Russia.
- (b) In response to this irrefutable evidence, the domestic industry made an interesting argument. Their argument that the subject imports from Japan have not hurt them as the customer who imported it from Japan is not their customer and hence they have not lost any market as a result of subject imports turns injury analysis on its head. The investigation is against a particular product and is not based on what the end use of the product is or who the customers are. Here we have a situation where a general product is sought to be investigated based on one end use and on top of it with reference to who the customers are. Such an injury analysis is unheard of in any anti dumping investigation in any part of the world. The Authority should ask the fundamental question as to whether the causal link has to be analysed in the manner indicated by the petitioner company. If imports have come from a non targeted country at a much lower price, it is inconceivable that such a price had not undercut the price of the domestic producers. If the argument of the petitioner is accepted, then the higher prices from Russia, China and Ukraine could not have undercut the prices of the petitioners. The causal link is, thus, conspicuously absent.

**45. Submissions made by the domestic industry**

In reply to the argument made above, it has been argued that in para 3 of Annexure II (iii) of the Anti Dumping Rules, provides that in case imports and

products from more than one country being simultaneously subjected to anti dumping investigation, DA will cumulatively assess the effect of such imports if he determines that:

- (a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than 2 per cent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the imports of the like article or where the export of the individual countries less than 3% the imports cumulatively accounts for more than 7% of the imports of like article, and;
- (b) cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles;

46. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the limits prescribed above. Quantum of imports from various countries have been as under:-

Country	Imports volume in MT	Share of total imports
Russia	18859	60.97
China	1680	5.49
Ukraine	1739	5.68
Other than subject countries		
Japan	8515	27.85

47. It is evident from the above that the quantum of imports from each of the subject country is more than the *deminimus* limit. Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the export prices from the subject countries directly compete with the prices offered by the domestic industry in India. The DA is therefore requested to assess injury to the domestic industry cumulatively from the subject countries.

48. **Examination by authority**

The analysis of injury caused by dumping has to take into account both the price and volume effect of allegedly dumped imports. In this context as is clear from the submissions made by the domestic industry and also verified by the DA, the volume of imports of subject goods from subject countries is significantly more than volume of imports from Japan. This implies that these imports from the subject countries have led to erosion in the market of the domestic industry even though Japanese imports may also have had similar effect. Further, in terms of price effect, even though the price of import from Japan is lower than the price of import from subject country, especially Russia, this does not imply that the analysis of price effect of the Russian exports is of no consequence. While arriving at a decision regarding the injury caused by the dumped imports from subject countries to the domestic industry, these factors have to be taken into account.

It has been the practice to assess the injury cumulatively from the subject countries in the course of the investigation as per the provisions in Rules mention supra. In this case the argument of interested parties opposing the petition is that one of the countries not subject to investigation is causing injury as their price is

much lower than export price of the countries subject to investigation. However, existence of injury from exports from Japan does not imply that no injury can be caused by exports from countries subject to investigation. This is more so when the landed value of exports from the subject countries is less than the fair selling price of the domestic industry. In view of the above, the argument of the interested parties opposing petition is not acceptable to the DA and the evidence available clearly shows that there is a causal link between dumping from Russia and China and injury being caused to the domestic industry.

#### **K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES**

49. The purpose of anti dumping duties, in general, is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

50. It is recognised that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. Imposition of anti dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

## L. CONCLUSION

51. After considering the foregoing, the Authority concludes:

- (a) Exporters from Russia and China have been exporting subject goods below normal value resulting in dumping;
- (b) The Indian industry has suffered material injury;
- (c) The injury has been caused cumulatively by the dumped imports of subject goods from the Russia and China;

Subject goods here are defined as "*certain grades/types of alloy and non alloy steel billets, bars and rounds of sizes 70 mm to 250 mm diameter conforming to IS specification or any other international specification equivalent to IS standards.*" List of these grades is given in paragraph 7 above.

52. It is considered necessary to impose anti dumping duty provisionally, pending final determination, on all imports of subject goods as mentioned above originating in or exported from Russia and China.

53. The DA has, therefore, decided to recommend anti dumping duty equal to the margin of dumping on the subject goods from Russia and China as per the amounts mentioned below pending final determination:-



Country and exporter	Amount of anti dumping duty recommended (US\$ per MT)
<b><u>Russia</u></b> (i)M/s. Oskol Electrometallurgical Combinat (OEMK)	16.03
(ii) Other exporters	148.50
<b><u>China</u></b> All exporters	179.14

54. It is proposed that these provisional anti dumping duty be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on subject goods mentioned above.

#### L. FURTHER PROCEDURE

55. The following procedure would be followed subsequent to notifying the preliminary findings :

- (a) The Authority invites comments on these findings from all interested parties and the same would be considered in the final findings;
- (b) Exporters, importers, petitioners and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make known their views, within forty days of the dispatch of this

notification. Any other interested party may also make known its views within forty days from the date of publication of these findings.

- (c) The Authority would disclose essential facts before announcing the final findings.

L.V. SAPTHARISHI, Designated Authority